

ascertain whether the member has the leave of the House. The Chair shall declare that since the mover has not pressed the motion, it shall be deemed to have been withdrawn by the leave of the House.

12.57 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT OF REHABILITATION INDUSTRIES CORPORATION, CALCUTTA

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (SRI L. N. Mishra): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Rehabilitation Industries Corporation Limited, Calcutta, for the year 1965-66 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-clause (1) of section 819A of the Companies Act, 1956 [Placed in Library. See No LT-990/67].

REPORT OF COMMISSION OF INQUIRY re COLLAPSE OF THREE HOUSES IN DELHI

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Commission of Inquiry into the causes of collapse of three houses in Delhi on the 15th August, 1966. [Placed in Library. See No LT-991/67].

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, on this subject, regarding the report of the Commission of Inquiry into the causes of collapse of three houses in Delhi, I would like to point out that whenever such a report is laid on the Table, the action taken on the Commission's report should also be let known to the House. I would like to know from the hon. Minister whether any action has been taken in this case, or, is it still under consideration.

Shri Vidya Charan Shukla: Action is under consideration, and we are in consultation with the Delhi Administration; after the action is completed,

we shall definitely come before the House and report.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS  
EIGHTH REPORT

Shri Khadilkar (Khed): I beg to present the Eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.57½ hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION—contd.

Mr. Speaker: Yesterday, we had taken 1 hour 35 minutes on the Demands for Grants under this Ministry. There is a balance of 8 hours 25 minutes. There are only one or two minutes more for the House to adjourn. So, instead of beginning the debate now, we shall begin it after lunch.

12.58 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Four Minutes Past, Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

DEMAND FOR GRANTS—contd.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION—contd.

श्री जोला नाथ (बलरघर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ एंड एडिक्स्वर मंत्रालय की जो मांग है उन का समर्थन करने के लिये बका हुआ हूँ ।

### [श्री भोला नाथ]

इस सिलसिले में जिम्मेदार करते हुए मैं आप का ध्यान जब के प्लेनिंग का अमाना मुक्त हुआ उस की धोर के जाना चाहता हूँ। इस में कोई शक नहीं कि आजादी से पहले भी हिन्दुस्तान में कल्पना की गई थी कि हिन्दुस्तान की अकात की प्लेनिंग हो और उस समय १० जवाहर लास नेहरू कांग्रेस की तरफ से उस प्लेनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और मेरा खयाल यह है कि उसी की भूमिका में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो सन् 1950 के बाद यह कल्पना की गई कि हिन्दुस्तान के योजनाबद्ध विकास के सामने रख कर जनता को जामुत किया जाये। लेकिन मैं यह मानता हूँ पन्द्रह वर्ष के तबुल्ले के बाद कि हम ने बड़ी भूलें की, और वह भूलें इस प्रकार की हैं जिन का समाधान जल्दी से जल्दी करने की आवश्यकता है। मेरा खयाल तो यह है कि इमरजेंसी को, जिस को एकस्टेण्ड किया गया है इस बात के लिये काम में नहीं लाया जाना चाहिये कि हम किसी को सजा दें, बल्कि वह इस काम में लाई जानी चाहिये कि जो फूड्स मिनिस्ट्रीज को दिये गए हैं, वह एकदम से फूड ऐंड ऐग्रिकल्चर मिनिस्ट्री को दिये जायें। कारण यह है कि जो प्लेनिंग का नक्शा हमारे सामने धाया है जो कन्सेप्शन हमारे सामने धाया है वह बाहरी देशों का है योरपीय देशों का है। योरप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ऐसे देशों में तरक्की हुई, मशीनरी की तरक्की हुई जिन के उप-निवेश थे जिन्होंने कालोनाइजेशन किया था। वे अपने देश में सामान बनवाते थे और कच्चा माल बाहर के देशों से लेते थे।

योरप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो घसली खेती का नक्शा था हिन्दुस्तान का उसे हम भूल गये। हमारे वहाँ कहावत है कि :

“उत्तम खेती मध्यम वान  
अधम चाकरी भीष निधान।”

लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर इस का उल्टा हुआ है। हम भीष स्टेज पर पहुँच गये हैं। हम भीष मांगने तक पहुँच गये हैं। हम को सम्झनी मिलती है। हम पीसे की मदद देते हैं ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तीसरी बात की तरफ भी हम बढ़े हैं जिस को अधम कहा गया है। हम उस की तरफ ध्यान रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियाँ दिलायें। शहरों को भी देखिये गांवों की आबादी शहरों की तरफ चली धा रही है। मिलों और फैक्ट्रियों की नौकरिया बहुत बढ़ गई हैं। नतीजा यह हुआ कि हम बेराज की स्थिति में धा गये हैं। ज्यादा में ज्यादा लोग शहरों में इकट्ठे होने लगे हैं।

आज गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी जिन का हम पूरा ध्यान रखते हैं, बेराज की स्थिति में धा गये हैं। आज रेडियों बोल रहा था कि काफी बेराज गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने किये हैं। वह डी० ए० की मांग करते हैं। मैं धर्ज करना चाहता हू कि यह डी० ए० क्या बला है। वह यह बला कि ऐग्रिकल्चर प्रोडक्शन कम होता है और यहां के लोग बैठे हुए हैं वह सब शहरों के हैं और वही के लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं। कभी ऐडजर्नमेंट मोशन लाते हैं, कभी काल घटेगन नोटिस लाते हैं उन लोगों की पैरवी करने के लिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किसानों से ही क्यों उम्मीद करते हैं कि वह अपना गेहूँ आप को रुपये का 2 सेर बेचे। यह कोई समझ में आने वाली बला नहीं है। न उस को चीनी सस्ती मिलती है और न सीमेंट सस्ता मिलता है न उस को टीन की चूड़े सस्ती मिलती हैं। कल मैं सुन रहा था कि दुर्गापुर की प्रोडक्शन प्लेन की जो दूसरी स्टेज है उसे कम किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो कारोनेटेड वीड्स बाँची की बिला करती थीं वह कम हो गई है। किसी कास्ट-कार को नहीं किम रही हैं। यह 3600:७७

टन हो रही है। कोई चीज कास्तकार को मकान को ठीक करने के लिये नहीं मिल रही है। उन के पास छप्पर बदलने के लिये या मकान ठीक कराने के साधन नहीं हैं। लेकिन हम लोगों ने योजना इस तरीके से बनाई है कि हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यह ठीक है कि चीन पाकिस्तान ने हमारी आँखें खोल दी हैं। उस का नतीजा यह है हम लोग बेटी की तरफ कुछ ध्यान देने लगे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम शहरों की तरफ से थोड़ा हट कर फूड ऐंड एग्रिकल्चर की तरफ ध्यान दें।

अभी कुछ समय पहले श्री हनुमन्तिया भाषण दे रहे थे कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज को डी० ए० देने में गवर्नमेंट ने 53 करोड़ रुपये खर्च किये। अगर इतना ही राज्य सरकारें भी कर दें तो इस का यह मतलब हो गया कि 2 अरब रुपये खर्च हुए अगर इस 2 अरब रुपये को कास्तकारों को बांट दिया जाय तो हम देखते कि क्या स्थिति बनती है। मेरे पास खाद्य और कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है। उस में लिखा है कि दो लाख कुएँ बनाये गये। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान में जैसलमेर का जो इलाका है उस में लगभग दस इंच साल में बारिश होती है। मैं इसको भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि जहाँ छोटे भी बाघ बाघ दिये गये हैं वहाँ अगर दस इंच भी मान में बारिश होती है तो उस इलाके में गेहूँ पैदा होता है किन को खुडील कहते हैं। मेरे इलाके में पच्छीस इंच से ज्यादा साल में बारिश नहीं होती है। मैं खुद कास्तकार हूँ, गेहूँ पैदा करता हूँ। मैंने इस ड्राउट में, बिड-ड्राउट इरिगेशन और ड्राई कस्टीबेशन में करीब नौ सौ मन गेहूँ पैदा किया है। क्या बजह है कि हम तरकीब ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। बजह यह है कि मदद हम को नहीं मिलती है, पानी को रोकने के लिए मदद नहीं दी जाती है। मेरे बेट में भी एक बी कुधा नहीं है और न ही बिजली पहुँच पाई है।

बहु कहा जाता है कि दो हजार धाबादी वाले भी कसबे हैं या चार हजार धाबादी वाले जो कसबे हैं उन में बिजली पहुँच गई है। यह गलत बात है। मैं जानता हूँ कि पाँच पाँच धीर सात सात हजार धाबादी वाले कसबों तक में बिजली नहीं पहुँची है। कास्तकारों के साथ बिजली के मामले में भी बहुत बड़ा मजाक किया जाता है। मैंने इसके बारे में के० एल० राय साहब को भी कहा है धीर में कमेटी में भी हूँ धीर में आपको बतलाना चाहता हूँ कि कास्तकारों को कहा जाता है कि रात को बिजली लो। अब आप देखें कि जनवरी और फरवरी के महीने में उनको रात के समय बिजली दी जाती है। यह वह समय होता है जबकि कोई रात में बाहर जाना पसन्द नहीं करता है। गवर्नमेंट सर्वेस को आप तरकीब दे रहे हैं, डी० ए० दे रहे हैं, उनके लिये प्रायम के रास्ते धापने हीटर लगा दिये हैं लेकिन कास्तकार से धाप कहते हैं कि बेटी के लिए वह रात को बिजली ले, जनवरी महीने में रात में बिजली से धीर धपने बेतों में पानी दे। धाप जानते ही हैं कि बेटी खुए से होती है और बेटी करने के लिए क्या रिया बनाई जाती है। जब एक ब्यारी बन जाती है तो उसकी मदद से दूसरी ब्यारी में पानी बिया जाता है। ऐसा करने के लिए कास्तकार को रात भर खेत में खड़े रहना पड़ता है अगर वह बिजली से तो।

मैं आपको चुनाव के दिनों का अपना अनुभव बतलाना चाहता हूँ। जब मैं लोगों से वोट मांगने के लिए चुनाव के दिनों में गया तो सब से पहले वे यह कहने लगे कि हमारा इलाज को तब वोट लेने आओ। हमारे यहाँ पहले डाक्टर भेजो फिर वोट लो क्योंकि हमारे बच्चे तो नर्मनिये से मर रहे हैं और यहाँ कोई डाक्टर सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। इसी तरह से बेटी की सहायिकाओं के लिए उन्होंने मुझ से किसानों की कस्तकार लोग, गवर्नमेंट सर्वेस आदि जो

[श्री मोला नाथ]

होटों का बिज रात इस्तेमाल कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी इसका इन्तजाम है और जो मैंने अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन मुझे मालूम है कि मेम्बरों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है लेकिन यह कैसा मजाक है कि कास्तकार को जनवरी और फरवरी के महीने में कहा जाता है कि वह रात को बिजली ले और उसका इस्तेमाल करे। डा० राब ने मेहरवानी करके मुझे इसका उत्तर यह दिया है कि यह हमेशा का कीचर नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कास्तकार को रात में बिजली देने का कौन सा तरीका है? इस बात को आप हमें समझाये। इंडस्ट्री के लिये आप बिजली रात को दे सकते हैं, वप्टरों के लिए रात को दे सकते हैं, आप क्यों कास्तकार को जाइलों में रातमें खड़े कर मारना चाहते हैं। यह उसके साथ मजाक है। इसको आप ठीक करने की कोशिश करें।

प्लानिंग का जो नक्शा मैंने आपके सामने पेश किया है उसको आप एक बम उलटा कर दीजिये बेटी को उत्तम समझना आप बूढ़ कर दीजिये। इसको आप प्रथम स्थान दीजिये। ऐसा करने की आप में हिम्मत है या नहीं है यह देखने वाली बात है। पार्लियामेंट सुप्रीम है और वह चाहे तो इस बजट को इस दृष्टि से देख कर इस में भ्राम्यसूत्र परिवर्तन ला सकती है। मैं चाहता हूँ कि इसको आप देखें और आपका जो दृष्टिकोण है वह कास्तकार की तरफ ज्यादा होना चाहिये।

आज हम बेराब और पवरॉब की स्थित में हैं। पवरॉब तो जन संघ ने शुरू किया है और बेराब की कम्प्यूनिस्टों ने शुरू किया है। अब एक और बेराब होने वाला है। आपकी यह राय दी जाती है कि लेबी बसूल करो, पोम्पीरमेंट करो। किस लिए इसको किया जाय? यह कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल

लेबर को बिलाने के लिए इसको किया जाए। जाहिर बात है कि एक तरफ तो वे इंडस्ट्रियल लेबर की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब लेबी बसूल की जाती है तो फिर माराब हो जाते हैं और कास्तकार को बड़काते हैं कि लेबी मत दो। हम जानते हैं कि राजस्वान में जब लेबी बसूल करने की बात चली भी तो वहाँ पर गोलियाँ चली थीं। यह आसान बात नहीं है। एक मामली कास्तकार से कितना आप लेना चाहते हैं और उसके पास कितनी भूमि है वह भी आपकी देखना होता है।

मेरा खयाल है कि हर पचास व्यक्तियों के पीछे एक कुएँ की योजना बनाई जा सकती है। एक एक कुआँ धरर आप दे दे तो फिर जयड़ा खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एक और प्रकसनदी की बात यह कर दें कि ऊपर एक छोटा सा बांध बांध दे तो और भी अच्छा होगा। इसका लाभ यह होगा कि हमेशा वाटर सेबल ऊपर रहेगा और कास्तकार के लिए यह परेनियल सोर्स धाक वाटर सप्लाई होगा। यह बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दो लाख कुएँ आपने बनाये हैं। मैंने इसकी फीला कर देखा है। 1965 में आपने करीब 7.45 मिलियन टन भनाज बाहर से मंगाया है। अब इसको ले कर मैं राजस्वान के एवरैज से चलना चाहता हूँ। दस टन एक कुएँ से आसानी से भनाज पैदा किया जा सकता है। यह 270 मन फेकरीब होता है। हम 27 मन एक एकड़ में पैदा कर सकते हैं। अस्सी बीघे में भी नौ ती मन पैदा किया जा सकता है। आप कहते हैं कि दो लाख कुएँ आपने बनाये हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आठ लाख कुएँ आप बना दीजिये और आप देखें कि अस्सी लाख टन की जो कमी है वह तिरक चार लाख कुओं से पूरी हो जाएगी। कास्तकार आप से कुएँ माँगता है तो कोई मेहरवानी आप से वह नहीं चाहता

है। यह वाहता है कि उसको तकाबी में बचाया दे दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को घाप देते हैं मकान बनाने के लिए और सब से घाप इस सोन को तीस साल में बसूल करते हैं। इसी तरह से घाप किसान को तकाबी में और एक लम्बी अवधि में इसको बसूल करें तो घाप देखेंगे कि किस तरह से पैदावार बढ़ती है। मकान बनाने के लिए गहर बासों को जो कर्ज दिया जाता है उसको तीस साल में बसूल किया जाता है। मैं भी एक कोमोप्रेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ कंप्यूटर स्टोर का भी हूँ। गहरों की जो हालत है उससे मैं भी नाकिल हूँ। घाप जो कार्टे टर्म सोन किसान को देते हैं उसको उसे जुलाई अगस्त में देते हैं और मार्च में जल्दी से जल्दी फसल के बीके पर बसूल करना चाहते हैं छः महीने में उसको घाप बसूल करना चाहते हैं। मीडियम टर्म का जो सोन है उसको घाप दो डार्ड साल में बसूल करना चाहते हैं। जो लोग टर्म सोन है उनको घाप सात घाठ साल में बसूल करना चाहते हैं। गहरी लोगों से मकान बनाने के लिए दिए गये कर्ज को तो घाप तीस साल में बसूल करते हैं लेकिन इन से नाग टर्म सोन तक को सात घाठ साल में बसूल करना चाहते हैं इस तरह से कैसे खेती की तरफकी हो सकती है। अगर घाप चार पांच धरब रुपया कुएँ बनाने के लिए दे दें तो किसान को परमानेंट इनकम भी बढ़ जाएगी और उसकी हैसियत भी बढ़ जाएगी।

बैंड रिफार्म की बात भी की जाती है। बैंड रिफार्म की बात बहुत प्रासन बात है। हमने राजस्थान में इसको करके देखा है। जमींदारों और जागीरदारों से जो जमीन हथ लेना चाहते थे तब हमने दो बातें कीं। सब से पहले यह कहा कि बेबबली न हो। घाप भी आर्गिनेस पास कर सकते हैं कानून पास कर सकते हैं कि जो कास्तकार बैठा हुआ है उसे बेबबल न किया जाए। दूसरी बात हमने कहा यह की कि बैंक रेटिंग न हो लगान न बढ़ाया जाए। बैंड गहरों में होता है कि

मकान और बूकान का किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है उसी तरह से कास्तकार के केस में बैंक रेटिंग न हो। सिम्पोरिटी घाफ टैन्वार हो। इसके साथ ही साथ तीसरी बात यह भी जा सकती है कि कुएँ के लिए उसको तकाबी दी जाए। यह तकाबी ज्यादा नहीं होगी। मैंने कैलकुलेट किया है। बी साब कुओं के लिए पांच हजार के हिसाब से एक धरब के करीब यह होती है। एक धरब कोई बड़ी बात नहीं है।

घाप लोग यह पूछते हैं कि यह सकार कैसी है जो हर रोज टैक्स लगाती जाती है खर्च बढ़ाती जाती है। राजाघों का जब राज्य था तब रेवेन्यू और कस्टम से बे काम चला लेते थे। लेकिन घाप तो रोजाना तनज्वाहें बढ़ रही हैं पटवारियों की मास्टरों की क्लकों की बाबुघों की रोजना बढ़ रही है। साथ ही रिटायरमेंट की एज को 58 से बढ़ा कर 55 किया जा रहा है और इस लिए किया जा रहा है कि नीचे को जो लोग हैं उनको तरफकी मिल सके। इस तरह से जो एक्सपेंडीचर है उसको घाप बढ़ाते बले का रहे हैं। कास्तकार पूछता है कि यह क्या करें? उसका लगान बढ़ा दिया गया है यह कहा से पैसा लाये। घाप ने 2600 या 2700 करोड़ के नोट छापे हुए हैं। यह घापकी रिपोर्ट में है। 1965 की रिपोर्ट में है। उस में से भाधा रुपया घाप को चाहिये कि घाप कास्तकारों के लिए एलाट कर दें उन के लिए रिजर्व कर दें। तब भी घाप देखेंगे कि पैदावार बढ़ती है या नहीं बढ़ती है।

प्लानिंग का जो नक्शा है उसको घाप एथिकसचर थोरिक्टिव बनार्ये, जउ से घाप क्रांतिकारी परिवर्तन करे। मम्किन है कि घाप पर घाप जोर पड़ रहा हो। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूँ कि डाये साहब का मुस पर यह प्रभाव पड़ा है उन के द्वारा दिये गये भाषण का मुस पर यह प्रभाव पड़ा है जब यह सोसियलिस्टिक तीसादटी की बात कर रहे थे तो उसकः

[श्री भोला नाथ]

युक्त मर वह प्रभाव पड़ा है कि वह मार्क्स-सिस्ट सोसाइटी चाहते हैं। एक बार की बात है जिस तरह से विश्वर भे घकाल पडा है और इस संगी की बजह से लाभ बहापुर भी ने जय किसान जय जवान का नारा लगया था रूस में भी घकाल पडा था और तब बहा गोरकी ने भूख हडताल की थी। नेनिन ने तब उन से कहा था कि बप् भूख हड़ताल कर रहे हो जब तक सोव भूखों नहीं मरेंगे तब तक क्रान्ति नहीं होगी। इसलिए आप इस बात को छोड़ दो और क्रान्ति लाओ। हमारे आगे जो भी चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा भूखों मरें और यहा क्रान्ति हो। वह सारे रुपये को बेती से हटा कर इबस्ट्री की तरफ ले जाना चाहते हैं सहूणों की तरफ से जाना चाहते हैं और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर बेराब और पबराब करवाना चाहते हैं और सरकार को बेराब में डालना चाहते हैं। इन सब से बचने का रास्ता यह है कि आप क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनायें और बेती पर चौबी योजना मे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे।

मैं यद् भी कहना चाहता हूँ कि सिमेंट आप क्लए बनाने के लिए और बेती के काम के लिए दें। रती भर सिमेंट भी आप बबी बड़ी दस बीस मंजिली इमारतों के लिए न दें। आपको यह पता होगा कि सिबिल का कोटा सिमेंट का सत्तर परसेंट है और एधि-चलचर का सायद तीस परसेंट है। जो किसान है उसको सिमेंट समय पर नहीं मिलता है तो उसको तकावी भी समय पर नहीं मिलती है और अगर तकावी नहीं मिलती है तो सिमेंट भी नहीं मिलता है। इस वास्ते इन दोनों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। तकावी और सिमेंट उसको समय पर मिलना चाहिये। इन सब बातों पर आपका ध्यान जाए यही मेरा निवेदन है।

Shri N. B. Patil (Bhir): Spoke in Marathi\*.

श्री एन. बी. पटिल (होजिपारपुर) : इन में कोई शक नहीं है कि जब के यह फूड और एधीकल्चर के विभाग को बाबू जगजीवन राम जी ने संभाला है उन्होंने काफी प्राथमिक स्टेप्स लिए हैं। लेकिन इस देश के इतिहास मे जितनी इस वक्त गभीर स्थिति फूड और एधीकल्चर की हो गई है इतनी सायद कभी देखने में नहीं आई थी जो रिपोर्ट साया हुई है डिप्टी स्पीकर साहब उस को देखने से पता चलता है कि पिछले एक साल मे इस सारे देश ने जिनना बपया एक्जपोर्ट से कमाया था उतने रुपये का हमने फूड वेन्स का इम्पोर्ट किया है। इस पिछले एक साल में कोई 523 31 करोड़ बपया हमारा फूड वेन्स के इम्पोर्ट के ऊपर खर्च हुआ है। पिछले 20 साल में इतना बपया कभी इस फूड की इम्पोर्ट पर खर्च नहीं हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन के अन्दर हम ने 105 64 करोड़ बपया सिर्फ फ्रेट चार्ज के ऊपर खर्च किया है। इस के माने यह है कि अगर एक रुपये का अनाज मगाते है तो उस के लिए 28 नये पैसे जहाज का किराया देना पडता है। इस से पता चलता है कि कितनी गभीर स्थिति आज देश के सामने इस फूड के मामले में है।

एक और चीज जिस की तरफ मैं हाउस का और ध्यान दिखाना चाहता हूँ डिप्टी स्पीकर साहब, यह है कि इस सारे देश के अन्दर पिछले एक साल के अन्दर जहा हमने 10.36 मिलियन टन्स शुराक बाहर से मंगवाई है उस के मुकामिले मे हमारे सारे देश के अन्दर प्रोक्वोरमेंट कितना हुआ है? प्रोक्वोरमेंट के सिवाज से बँचे तो हिन्दुस्तान की आजादी के समय से लेकर

\*The Member did not furnish a translation of his speech in Hindi or English.

47 से के कर इस वक्त तक पिछले 20 साल के अन्दर हम ने पांच फूड ग्रेन एम्बार्गोरी और फूड ग्रेन पालिसी कमेटी बिठाई। एक कमेटी प्री-इंफ्लिपेंस डेज में बंगाल का कहत जब पड़ा था तब बिठायी थी और बार उस के बाद बिठायी है पिछले 22-24 साल के अन्दर प्री-इंफ्लिपेंस से लेकर इस वक्त तक। सिर्फ ब्रिटिश राज के जमाने में 42-43 के बाद एक बार कोई 5 मिलियन टन प्रोक्वोरमेंट हुआ था उससे के बाद 64 के अन्दर जो हमारा सब से अच्छा साल थाया था उसके अन्दर 4 मिलियन टन प्रोक्वोरमेंट हुआ। लेकिन वह भी सारे का सारा 65-66 में खरब हो गया। तो प्रोक्वोरमेंट के लिहाज से सब सब से पीछे है। और यह जो नया साल शुरू हुआ इस के पहले क्वार्टर में 22 लाख टन का इम्पोर्ट हम ने किया। जहा तक स्टेट्स का ताल्लुक है सारे देश के अन्दर इन वक्त तक कुल 27 लाख टन मारे का सारा प्रोक्वोरमेंट हुआ है। तो प्रोक्वोरमेंट के लिहाज से हिन्दुस्तान पीछे जा रहा है। इम्पोर्ट के लिहाज से हम घागे बढ़ रहे हैं। अगर हमारी यही हालत रहती है तो हिन्दुस्तान की एकोनामी की क्या हालत होगी? मुझे इस बात की हैरानी होती है कि जितने भी अर्पोजीशन बेनेज पर हमारे दोस्त बैठे हैं हर एक भावमी यहा आ कर गवर्नमेंट आफ इंडिया को इस के लिए कोपता है। लेकिन किसी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया है। इन बार अभी थोड़े दिन हुए जबकि यू० पी० के चीफ मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ने स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने यह कहा था कि इस बार यू० पी० के अन्दर जितना अम्पर क्राप हुआ है उतना पिछले 18 साल के अन्दर नहीं हुआ है। 45 लाख टन अनाज बर्हा हुआ 33 लाख के मुकाबिले में। 12 लाख टन ज्यादा हुआ। लेकिन प्रोक्वोरमेंट उस के मुकाबिले में कितना हुआ है? पंजाब के अन्दर इस बार इतना अम्पर क्राप हुआ जित की कोई हद नहीं है लेकिन उस के मुकाबिले में इस वक्त तक कितना प्रोक्वोर-  
1300 (A1) L&D-8.

मेंट हुआ है? 2.5 लाख टन सारा प्रोक्वोरमेंट हुआ है। सी तरह बाकी जगह धाप देखें। गान-कावेस गवर्नमेंटस है या दूसरी है, प्रोक्वोरमेंट उस के मुताबिक ठीक नहीं हो रही है। एक्सपोर्ट में सारा रुपया जा रहा है कहीं फ्रेट बार्जोब के अन्दर और कहीं दूसरी चीजों बुराक बारीदने में जा रहा है। तो हिन्दुस्तान की एकोनामी जिन हालात में है उस में हम क्या कर सकेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। और सिर्फ यही नहीं जो मैं केवल दो प्रान्तों की बात कर रहा था यह जो क्यूट जोन है नार्दन जोन का अगर हम पिछले तीन बार साल का सारा देखें 64-65 और 65-66 के मुकाबले में इस बार मार्केट के अन्दर क्यूट 14 परसेंट कम थाया है। राइस 7 परसेंट कम थाया है। इस के मानी यह है कि अनाज मौजूद है लेकिन किसी जगह छिया पड़ा है। होर्ड्स के पास छिया पड़ा है, जमीनदार के पास छिया पड़ा है या ट्रेडर्स के पास छिया पड़ा है किस जगह छिया पड़ा है मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात साफ है कि अम्पर क्राप होने के बावजूद अनाज मौजूद होने के बावजूद वह मार्केट में नहीं था रहा है और हमारे हिन्दुस्तान के सारे नेशनल एग्जिस्टेंस को एक चैलेज सा हो रहा है। हमारी एकोनामी को एक चैलेज मिल रहा है। मालूम नहीं हम किस हद तक उस को एक्सपोर्ट कर पाते हैं और मुकाबला कर पाते हैं। इस के मुकाबिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया का जहा तक ताल्लुक है सज्जिडी बढ़ रही है। 119 करोड़ रुपये से 130 करोड़ रुपये तक सज्जिडी घा गई है एक साल अन्दर। इस तरह कब तक यह चलेगा? इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब आप के मार्फत मैं अपने मिनिस्टर साहब से और हाउस से कहना चाहता हूँ कि वक्त था गया है कि इस सवाल को हम एक नेशनल प्वाइंट आफ व्यू से देखें। इसे प्राविनियल प्वाइंट आफ व्यू से या दूसरे किसी प्वाइंट आफ व्यू से न देखें। पिछले सात आठ साल के अन्दर जितनी चीफ मिनिस्टर

## [श्री राम किशन]

कान्फरेंस हुआ है और इस जनरल एसेसमान के बाद दो चीफ मिनिस्टर्स कान्फरेंस हो चुकी है इनमें जितने भी फंसले हुए उन पर कितना प्रमल हुआ है। अभी मैंने फूड ग्रेन्ड पालिसी कमेटी की बात कही उन के जितने डिस्-चन्स हुए हैं चीफ मिनिस्टर्स के जितने डिस्चिज हुए हैं अगर उन में से एक डिस्चिजन पर भी प्रमल हो जाता तो शायद हिन्दुस्तान का उस से ज्यादा भला होता।

नवम्बर, 1966 में चीफ मिनिस्टर्स की कान्फरेंस हुई, जिसमें उन्होंने फंसला किया कि हम चार सालों के अन्दर 1 करोड़ 20 लाख टन प्रोक्वोर कर के हिन्दुस्तान का एक बकर-स्टॉक बनायेंगे। अभी 8-9 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर्स की कान्फरेंस हुई, उस के अन्दर भी कुछ फंसले किये गये—उस में एक फंसला उन्होंने यह किया कि हम सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इन्टेंसी-फाई करेंगे, माइनर इरिगेशन पर जोर दिया गया। गवर्नमेंट फ्रांज़ इण्डिया ने इस के लिये 120 करोड़ रुपया दिया लेकिन चीफ मिनिस्टर्स कान्फरेंस की जो हाल की कार्यवाही निकली है उस से पता चलता है कि जहाँ तक स्टेट्स का ताल्लुक है वह कहते हैं कि हमारे पास रिस्सोर्सेज नहीं हैं और जो हिस्सा स्टेट्स को 120 करोड़ रुपये में प्रदा करना था, वे उस को प्रदा करने को तैयार नहीं हैं। लेण्ड रेवेन्यू खत्म हो रहा है, प्रक्वोर-मेन्ट हो नहीं रहा है, फ्रांज़रि फिस तरह से हम उस के मुताबिक सारी चीजों को कर पायेंगे, समझ में नहीं आता है। इस लिये, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब अब बन्त घा गया है कि हम इन सारी चीजों पर गौर करें कि फ्रांज़रि हम जा कहाँ रहे हैं कहाँ हम को क्लुपना है ?

बन्त हमारी क्या हालत है ? हमारे क्लुपनी क्लुपनी

लैड हम पूरा कर सकते हैं—इस बन्त 43 परसेन्ट लैड है जिस में हम क्लुपनीयान कर रहे हैं—दुनिया के किसी मुल्क में इतनी धरती में काश्त नहीं होती है, लेकिन उस के बाबजूद भी हालत क्या है। ज्यादा से ज्यादा जमीन हमारे पास है, 6 करोड़ फमिलीय का कृषि का काम करती है लेकिन उस के मुकाबले जहाँ तक ईल्ड का ताल्लुक है वह दुनिया में सब से कम है। मैं इस की दो मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ—जापान, एक ऐसा देश है, जिसमें ज्यादातर पहाड़ हैं और इसकी बजह से वे अपनी सारी जमीन को काश्त में नहीं ला सकते हैं, 16.4 परसेन्ट जमीन को वे काश्त के अण्डर बायें हैं, बहा की सिर्फ 33 परसेन्ट आबादी काश्त करती है, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, आप यह सुन कर हैरान होंगे कि 16.4 परसेन्ट जमीन पर काश्त करने वाला जापान आबाद पदावार में सब से धागे है, उस की आबल की पदावार दुनिया में सब से ज्यादा है। सारे जापान के लिये रैल्फ सफिशियेन्ट होने के बाबजूद वह सरप्लस मुल्क है।

अमरीका की क्या हालत है। वहाँ पर एक किसान इतना पदा करता है कि अपने भलाबा 25 आदमियों के लिये पूरी तरह से खुराक देता है, तीन आदमी जो विदेश में हैं उन को फीड करता है और फिर भी बाकी बचाता है। लेकिन हिन्दुस्तान में 20 साल के बाद यह हालत है कि 7 किसान रात-दिन करने के बाबजूद भी 10 आदमियों को फीड नहीं कर सकते हैं।

मैंने आपका का चिन्त किया, लेकिन आप हिन्दुस्तान में देखिये—ज्यादा पंक्चर का सिन्ड्रोम का इलाका हो या म० पी० का इलाका का इलाका हो, वे इलाके हमारे जहाँ सब से ज्यादा आबल पैदा करते हैं, लेकिन हम आबल के मुकाबले तीन गुना ज्यादा जमीन इस्तेमाल करके भी इतना आबल पैदा नहीं कर पाते,



विश्वना जापान हम से एक-तिहाई पानी इस्तेमाल कर के पैदा कर लेता है। इस की वजह क्या है ? हमारे यहाँ वाटर का यूटिलाइजेशन एफिशियेन्ट नहीं है कम है और पानी का नुक्सान होता है।

जहाँ तक खाद का ताल्लक है, हमारे बहलं दुनिया के मुकाबले में सबसे कम (फी एकड) इस्तेमाल होती है, अगर हम सारी दुनिया की एजेंट में तो दुनिया के मुकाबले में खाद का इस्तेमाल कर पाते हैं। धारमी के निहाज से जमीन के निहाज से टैकनीक के निहाज से सब कुछ हमारे पास है लेकिन उस के बावजूद भी हालत यह है कि 20 साल में हमारी हालत में कोई तरक्की नहीं हुई, हम नीचे की तरफ हो जा रहे हैं। इस की क्या वजह है ? इस के मायने साफ है कि हमारे यहाँ कुछ खराबी है। बुनियाबी खराबी है, बेसिक खराबी है, जिसको हम दूर नहीं कर पाये हैं। एक सब से बड़ी खराबी यह है कि आज दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं जापान, कोरिया, अमरीका वगैरह, वे जिन मॅन्ड्स का इस्तेमाल अपने यहाँ एपीकल्चर में करते हैं, हम उन मॅन्ड्स का इस्तेमाल अपने यहाँ नहीं कर पाते हैं। जब तक इस देश में एपीकल्चर के अन्दर तरक्की नहीं होगी, यह देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। असल बात यह है कि आज की गवर्नमेन्ट को एपीकल्चर के मसले को एपीकल्चर के तौर पर नहीं, बल्कि इण्डस्ट्री के तौर पर कन्सीडर करना होगा, बल्कि उस को पूरी तरह से इण्डस्ट्रीयलाइज करना होगा, तब जा कर सारा काम चल सकेगा।

जब मैं इस बात का खिन्न करता हूँ कि अमरीका, जापान या दूसरी एडवन्सड कन्ट्रीज में किस तरह से इस सारे सिलसले को चलाया है, की मुझे खुशी है कि आज एपीकल्चर की भी नई स्ट्रेटिजी हमारी गवर्नमेन्ट, हमारे कुछ मिनिस्टर साहब सम्भव कराने ला रहे हैं, वे इन सात-आठ

चीजों पर भी, जो अमरीका, जापान या दूसरी एडवन्सड कन्ट्रीज ने अपने ऊपर की हैं, तबल्जह देंगे वे हैं—

adaption of machinery and technological inventions in farming,

increasing application of scientific and technological methods to agriculture;

agricultural education, heavy use of fertilisers;

mechanisation, improved varieties of crops and livestock, better seeds better irrigation and drainage, better methods of controlling weeds and pests Implementation of research result in farming

अब आपकी मारफत, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करना चाहूँ हूँ हम में इस देश के लिये जिस तरह का ध्येय बनाया है, जिस तरह का टारगेट बनाया है कि सन् 1970-71 तक हम इस देश को सेल्फ सफिशियेन्ट बनाना चाहते हैं, सरकारी आकड़ों के मुताबिक जितनी हमारी प्रोडक्शन है या जितना खाना हम खाते हैं, उस में 24 मिलियन टन की एडीशनल जरूरत होगी। इस नई हार्ड-वेड-बैरायटीज की मदद से 1970-71 तक, जो फॅक्ट्स एण्ड फिगरस दी गई हैं, उन के मुताबिक 32.5 मिलियन एकड जमीन से हमें इन नई वॉइटीज को ले जाना है। अगर हम इस काम को पूरी तरह से सरजाम दें, तो फिर 24 मिलियन टन ही नहीं, बल्कि उस के अन्दर 25.5 मिलियन टन हम ज्यादा पैदा कर सकेंगे। अब सवाल है कि किस तरह से कर सकते हैं ? इसके लिये तीन-चार अर्थ हैं और इस मिनिस्ट्री को उस बेलेज को मुजुम कर के उस को करना होगा—सब से पहली चीज तो यह है कि जहाँ तक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है, मिनिस्ट्री की देखना होगा कि वह फर्टिलाइजर

[श्री राम किशन]

की पूरी तरह से देने के लिये सवार है या नहीं 1970-71 तक जितने फर्टीलाइजर की जरूरत है, जितना धाज हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 20 लाख टन नाइट्रोजन की भीर जरूरत होगी, इसी तरह धीर भी चीजें जैसे फास्फेट थाफ गोटोसियम है इनकी जरूरत होगी, जिसको पूरा करने के लिये 487 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 194 करोड़ रुपये फौरन-ग्लबलेशन धापको देना पड़ेगा, इन सब का धापको इन्तजाम करना होगा। अगर 1970-71 तक के ध्येय को पूरा करना चाहते हैं तो फिर जहा तक फर्टिलाइजर का ताल्लुक है, देश के किसानों को यकीन दिलाना होगा कि इस अर्थ में उन को जितना फर्टीलाइजर चाहिये, वह धाप मुहिया करेंगे। अगर धाप फर्टिलाइजर देने को तैयार नहीं होंगे तो यह सिलसिला चलने वाला नहीं है। इस लिये मैं धाशा करता हूँ कि धाप इस तरह पूरी तबज्जह देगे।

धाप 1969 में महारमा गांधी की सेन्टेनरी मनाने जा रहे हैं। धाज जिसकी बबोसत हम यहां पर बैठे हुए हैं उसके मुताबिक फौसला करे कि हम हिन्दुस्तान को सेल्फ-सफिकियेन्ट बनायेंगे धीर उसके लिये जिन जिन चीजों की जरूरत होगी हम उनको मुहिया करेंगे। जिन चीजों की खास तौर पर धापको जरूरत होगी मैं उन चीजों की तरफ धब धापकी तबज्जह दिताना चाहता हूँ—वे 10-12 चीजें हैं में उनको डिटेल् में नहीं जाऊंगा, लेकिन धापसे दरब्बास्त करना चाहता हूँ कि धाप उन पर पूरी तरह से भ्रमस करे, ताकि हमारा यह सिलमिला तेजी से चल सके—

1. गारण्टीड प्राइस पालिसी धाप किसानों को पूरी तरह से यकीन नहीं देते हैं कि धाज क्या प्राइस होगी धीर कल क्या प्राइस होगी। धापको एक गारण्टीड प्राइस पालिसी एभाउन्स करनी होगी, ताकि किसानों को पता चल जाय कि उन को 1970-71

तक क्या प्राइस मिलेगी।

2. स्पेसलाइज्ड एक्सटेन्सिव एण्ड टैक्निकल एपीकल्चर सर्बिस—इस काम की बोझा खोर से करना होगा। सारे ए.ए. टेन्सिव प्रोग्राम को स्ट्रेन्चन करने के लिये इस पर खीर देना होगा। कम्प्यूनिटी ब्लाक धीर धाम सेबकों को यह भी मासुम नहीं है कि किसानों को किस तरह का नौसिज देने की जरूरत है, कहां से इन-मुट्स धायेंगे इनकी तरफ खास तबज्जह देकर इनको स्ट्रेन्चन करना होगा।

3. फर्टिलाइजर—इस के लिये मैंने धभी धापके सामने जिक्र किया है।

4. एफिकियेन्सी इन यूटिलाइजेसन धाक वाटर—इस के लिये डिटेल् में न जाते हुए मैं यह अर्थ करना चाहता हूँ कि कैनेडोनिया ने धापने यहां वाटर सिस्टम का कोड बनाया है उस को धाप पूरी तरह से महेनजर रखें धीर देखे कि एक-एक कतरा पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके।

5. फार्मज ट्रेनिंग

इनके धलावा दो बाटें धीर हैं। धाज हमारे देश में जिस तरह से यह धंधा चल रहा है यानी जोन का जो सिस्टम है उस ने भाई से भाई को जुदा कर दिया है। हिमाचल की धजीब हासत है येरी धपनी कोस्टीचुएसी—होशियारपुर की यह हासत है कि जिन पहाड़ों ने ईम दिये जिन पहाड़ों ने पानी दिया, जिनकी मदद से सिंचाई होती है, लेकिन उनको उस के मुताबिक धनाज नहीं मिलता। सिर्फ यही नहीं मैं धापसे पंजाब का जिक्र करता हूँ। नंगल डैमके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने एक बैरियर लगा दिया है। नंगल डैम के उखर कोई 80 ए० क्विन्टल्स नेहूँ मिलता है लेकिन जहां पर नंगल फौट्री है वहां 150 धीर 160 ए० क्विन्टल्स भी नेहूँ नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश की भी यही हासत है। इसलिये मैं धापके जरिये से निमिस्टर वाहल

के वर्ष करना चाहता हूँ कि बहुत ज़ादवा है जब कि एक नेशनल कमिशन मान फूड सेल्फ-सफिशिएन्सी कायम किया जाय जिस के सदस्य पूरी तरह से एक्सपर्ट्स हों। और एकानमिस्ट्स हों और सब चीजों को देख करके वह तय करे कि फूड जोन्स किसी ढङ्ग में कायम रखने हैं या नहीं रखने हैं। हिन्दुस्तान की यकजहती इंटिग्रेसन के अयाल से आप इस को देखिये।

आज अजीब हालत हो रही है कि जो 10 परसेन्ट अनाज बाहर से आता है उसकी प्राइस पर हमारा कंट्रोल है लेकिन जो 90 परसेन्ट अनाज हिन्दुस्तान में पैदा हो रहा है उसकी प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है। 1962 में आइनीज एग्जेशन के बाद जो नारा लगाया गया था कि प्राइस-लाइन इस बिनाइफ-लाइन आक बिनेशन सेट अस होल्ड इट। कहा गई वह प्राइस लाइन जो कि हमारी साइफ-लाइन थी? वह और भी बढ़ती जा रही है।

इस लिये मैं आपकी मार्केट मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि अब बहुत ज़ादवा है कि हम इन सारी चीजों पर गौर करे। अगर हमको फूड के अन्दर सेल्फ सफिशिएन्सी हासिल करनी है तो जिन जिन चीजों की जरूरत है किसान को किसान को वह सब चीजें दें। इस देश की इएकानमी को बचावें और देश के अविष्य को भी उज्ज्वल करने की कोशिश करे।

**Shri H. P. Chatterjee (Krishnagar):**  
Mr. Deputy-Speaker, Sir, our total import in the third Five Year Plan was to the tune of Rs. 1,033 crores, of which the PL-480 imports were Rs. 849 crores. In 1966 alone, we had imported 10.36 million tons valued at Rs. 523.31 crores, of which PL-480 imports were 80.3 lakh tons valued at Rs. 343.1 crores. We pay 35 dollars for each ton of food that is being shipped from the USA.

Our production in 1964-65 was 89 million tons; 1965-66, 72 million tons; 1966-67, 76 million tons. If there was no drought, we assumed that we would get in 1968-67, 90 million tons. Our requirement at the end of the fourth Five Year Plan is 120 million tons. That is, we shall have to produce six million tons more per annum. But in the case of our agriculture, only a stepmotherly attention is given. The third Five Year Plan laid stress on agriculture, but plan priority is not observed by the States. Once they go to the States, the plan priority is shelved and thus the planning papers became only a farce.

In 1964, our national income was Rs. 16,630 crores. We got from agriculture Rs. 7,462 crores, that is, nearly half. Yet, we spent only 10 per cent on agriculture. For agricultural education, we spent Rs. 30 crores as against Rs. 142 crores on technical education. That is also 10 per cent. For research on agriculture we spend very little of science budget. In Australia and New Zealand, 45 per cent of the total science budget is spent on agricultural research. Our community development programme is an American pill that we have swallowed. We have imported sahebs into the villages, non-technical men, who know nothing of agriculture. They cannot advise 66 millions of agriculturists spread over 56 lakh villages.

What to do? We shall have to produce 120 million tons at the end of the fourth plan. We must go in for intensive cultivation, because we have no land for agriculture. It is not my saying. I initiated the discussion on the agriculture budget in 1963 and in his reply on 21st March, 1963, Shri S. K. Patil said:

"In India, not now, but for all time, to come, there is no land for agriculture. Even more, if any land is available, I shall rather use it for forests and not for agriculture. If there is total destruction or diminution of forests, agriculture can never make

[Shri H. P. Chatterjee]

any program. In our country, forests should be somewhere about 50 per cent at least. It has gone down to 30 per cent; sometimes it is 18 to 23 per cent. I do not know what is the correct figure. If there is any possibility of utilising more land for forests, I as Minister of Food and I think even the Minister directly in charge of forests, Dr. Ram Subhag Singh—we are of the opinion that more land should be given to forests in order to stabilise the condition of agriculture and no land should be taken away."

Profession and practice are different. Taking 1950 as the base year with 100, we find that cultivated land has gradually gone up in 1963-64 to 122.7, i.e. an increment of 22.7 per cent. The percentage of our cultivated land is about 47. We should have forests of about 33 per cent. We should reduce the cultivated land to 33 per cent. That is the forest policy which we have accepted. But in actual practice, what do we do? We go on increasing production in marginal soil and thereby we harm our agriculture. God should not be blamed for the drought, but we should be blamed because we cut down all the forests. Forests bring in clouds because of the transpiration they do. But we destroy the forests like anything. Many civilisations in the past have perished because they have destroyed forests for colonisation and for agricultural land. This is a historical fact. Here is a book published by UNO—*Rape of Earth*—which shows clearly how civilisation in Persia, North China and Mesopotamia perished because they cut down forests. Trees are the emblem of humility. They also give shade, even when we cut them down. But in our vandallism, we cut down the trees. We have created an imbalance in nature. I had toured in Palasnau district and Hazaribagh district. You cannot get

a drop of water there because there is no forest. Where there is forest, you will find water. Otherwise the river beds are also dry.

15 hrs.

Anyway, Sir, we must remember that in Japan 67 per cent is under forest, in the U.S.S.R., it is 45 per cent and in Europe it is 41 per cent. Ours is the lowest in the world. We have 805 million acres of land in India and of that 139.5 million acres are under forest. That comes to only 17.2 per cent.

India is in the grip of soil erosion. One hon. friend from Punjab was saying how chos and gullies have formed there. In India 200 million acres are under soil erosion. That means one-fourth of our total land is under soil erosion. In the Siwalik foot-hills of Hoshiarpur District in Punjab, forest has been cut down. What happened? Chos and gullies have appeared in that most fertile land due to soil erosion and it just expands in geometrical progression. In 1852, in the Siwalik foot-hills, in Hoshiarpur, Punjab, gullies were 75 square miles. It went up to 1700 square miles nearly ten times by 1939, within less than a century. You also know that in Chambal ravines, which are now the bandits home, and also in the Etawah ravines, the Indo-Gangetic plains, about 8 million acres of land can be reclaimed and formed into very good cultivable land. It may be converted into our granary. So, not only here but in all places soil erosion comes in.

Our late Chief Engineer of the Central Water and Power Commission, Shri Man Singh, in his Flood Committee Report has written:

"If soil and water conservation programme is postponed for one year at least half million acres of good land will be lost forever."

Now I come to one main thing and that is irrigation. If we go in for intensive cultivation we must go in for irrigation. Irrigation is the first thing necessary and we are losing our irrigation potential like anything. Our outlay in river valley projects including power, irrigation and other things is about Rs. 3000 crores. All these are in danger. What will happen to these in the near future nobody can say. Our experts say that the Bhakra dam where we have spent more than Rs. 200 crores is dying. I have got here an article by Sardar Partap Singh, IFS, Retired Forest Officer. I do not want to quote everything. It was published in Statesman in August 19, 1965 under the heading: "Saving Bhakra Dam from premature death—Forest conservation the only effective method—Bhakra Dam is dying". This is what a just retired manager of Bhakra Dam said on Bhakra Dam at the Simla Flood Control Seminar in 1962. Siltage is 87 per cent more than was calculated. So, something must be done about it. What is the good of going in for new irrigation when we cannot save our existing projects?

Mr. Deputy-Speaker: He should try to conclude.

Shri H. P. Chatterjee: I have 26 minutes because I am the only speaker for the Progressive Group. If you disturb me it will be difficult for me to continue my speech. I would rather sit down. This is my subject. Further, I have not spoken for more than 7 minutes. I have seen the clock.

Mr. Deputy-Speaker: He has taken 14 minutes. If he wants to exhaust the whole time of his Group, I have nothing to say.

Shri H. P. Chatterjee: Since there are so many members in the Progressive Group, after calculation 26 minutes have been allotted to us. I am the only speaker for my Group. If I am not given that much time, it is better that I go out from Parlia-

ment, it is better for me to resign. When I was an Independent, I had no locus standi; I was a second-class Member here. Now, when I join a Group, then also no time is given to me. Then, how can I work? I shall speak for 26 minutes of my time and 4 minutes from you, half an hour in all. Please, do not disturb me. This is a very important subject.

We have spent so much money on these projects and now our Ministers are sleeping over them. I have seen that they have become golf courses. If you come along with me to Tilaya, Mython and to other dams in winter and see the dried up live storages, you will find that they are just lying as golf courses. You cannot see any vegetation there on the catchment area. What is the good of creating new irrigation dams and all that, when we cannot check siltage up of the existing dams because of soil erosion? Our Parliamentarians should know that this is wrong.

On account of the shortage of time, I am not able to refer to soil erosion in detail. Soil erosion is not static; it is dynamic. Erosion varies as the square and the transported material as the sixth power of velocity of water flow. Suppose the velocity is increased ten times, then soil erosion would be 100 times and material transported will be increased to the good figure of a million. We have very big engineers, experts on building dams, they do not know these things. Everything is mentioned in this Book and I feel like reading it. But I check myself because I have other matters to deal with.

Now in what condition are we? Here we find that velocity is creating havoc. Rains fall on the earth and this is like bombardment. Our first line of defence will be these millions of tremulous green leaves of the forests on the catchment area. If the catchment area is denuded of trees, what will happen? This rain will fall

[Shri H. P. Chatterjee]

on the earth directly and it has been established by science that if water on account of rain falls on earth which is bare trickle by trickle within a few years the surface of the earth would vanish, because the vegetables keep the mineral matter in position. The trees are our first line of defence and we are losing them every year. This is the position not only in Bhakra; in DVC it is twice that much. I have toured that area with Mr. Gouri, who was the Chief Soil Conservator. It is my hobby. Out of the 7,200 square miles of catchment area, a major portion I have toured. These portions are denuded of trees which has brought in havoc. Mr. Gouri pointed out that if you just spent Rs. 19 crores you will get an income after ten years of Rs. 1½ crores. So, this will be a sort of insurance and, at the same time, you will be able to save the dams. But, what is happening now? On the average annually three acre feet silt comes in one sq mile

Now, we have 25 river valley projects and the catchment area is 3 lakh square miles. It is not of my working but the figure is supplied by our experts. In June 1964 I was in Srinagar to attend the soil conservation meeting going on there. I do not know whether my hon. friend, Shri Shunde, was there or not then. Shri Desappa was presiding over it. I was the only speaker from amongst Members of Parliament because other Members of Parliament did not attend it. I went alone only because it is my subject. What I found there was that our experts were demanding that at least 10 per cent of the catchment area must be afforested within 15 years otherwise our valuable dams, our national monuments, will vanish in no time and we will have no irrigation. They demanded Rs. 363 crores for that. Here I have that literature. It was supplied there in that conference. I have very little time to open it now; I must hurry up. But here they have pointed out

that it is very necessary. Our experts, all unanimously, wanted that.

But what happens? Because they are not the masters—it is the Finance Ministry—some people there in the small room sit who think they know everything and they do not grant the money. What will these people do? They have calculated this and this is not a very unreasonable calculation because everywhere in the world, wherever they have prepared dams, they have reserved 10 per cent of that for afforestation.

Even at Bhubaneswar where on 31st December 1960, a conference of all our States Ministers in charge of agriculture was held, which was presided over by the Union Agriculture Minister, it was recommended that 10 per cent of the money on river valley projects should go for soil conservation work. But profession is one thing and practice is another. Nothing is being done. What have you granted? In the Third Five-Year Plan you granted only Rs. 11 crores for all the dams and in the Fourth Five Year Plan you have recommended only Rs. 19 crores. How can you expect that the thing will go on?

What is happening? I was saying that for one square mile, it has been found by our experts, the average sedimentation is 3 acre-feet. In this 3 lakh square miles catchment area, what will be the sedimentation? You can very well understand that. It will be near about a million acre-feet. If a million acre-feet sedimentation comes in, half of it at least will go to live storage; that is, 5 lakh acre-feet will be reduced of the total live storage. And the reduction of live storage is a serious matter because one acre-foot of water in live storage gives 1½ acre-foot of water for irrigation. That means, we will lose irrigation potential of 7,50,000 acre-feet.

Shri E. Sarma: What is live storage?

Shri H. P. Chatterjee: Annually it is that much. To create one acre-foot of water in live storage—here is the calculation of our experts—we require Rs. 600; that is, for 5 lakh acre-feet we are losing annually Rs. 30 crores. If you capitalise that, what will happen? You have taken the life of the dams to be hundred years. That means, it will come to Rs. 3000 crores. Therefore no expenditure should be grudged in protecting these water resources. You are not doing it. If you lose so much irrigation potential, why do you run after other projects?

Then, we have got the DVC on the lines of the Tennessee Valley Scheme. There in the T.V.A. was 54 per cent afforestation, even then they thought that if they did not go in for further afforestation, they would be doomed. There the country is hilly just like what you will see if you go to Hazaribagh and Palamau areas. Here the rocks lose all the soil. There is no cover and the ram bombards. You do not have the first line of defence. What is the first line of defence? It is these tremulous green leaves. Millions of leaves will hold millions of rain drops and the forest will just bring the humus there underneath, which will retain the water and all mineral matters. Here, I am very much tempted to read what the well-known Hydraulic Engineer, Mr. H. G. Morgan, of the T.V.A. says. He says:

"Dams are good but if we could raise the underground water table of the Tennessee Valley by only 6 inches, that would mean 26 million acre ft of water—four times as the Norris reservoir (biggest in T.V.A.) will hold. Nature would do the storing."

It has been calculated that 100 sq. miles of tropical or sub-tropical forest would absorb approximately 4 million acre ft. of water, a quantity half the capacity of Bhakra Dam. Bhakra Dam has got a capacity of 8 million

acres, from Ruper to Karachi 1000 miles long, 2 miles wide and 6 ft. deep. As regards silt, there is no afforestation on the hills and your Bhakra Dam is silted up. I cannot fail to read this calculation of Sardar Partap Singh:

"But the object of writing is not to fix an age for Bhakra dam which is not easy of calculation but to warn that it is most likely to be reduced from a possible 600-700 years to a mere 50 or 60 (not 70) which was the true meaning of the cry, "Bhakra dam is dying" unless we take immediate remedial action . . ."

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up

Shri H. P. Chatterjee: I have yet to speak on many things.

Mr. Deputy-Speaker: You can have 3 minutes more.

Shri H. P. Chatterjee: Give me 5 minutes more

I will not touch many other things. About fertiliser, on an hectare, we use 1/7th of the average world consumption of fertiliser per hectare. This is the lowest in the world. In a sense I do not mind it because if you use more fertiliser in an unscientific way, the land will be spoiled. As Mr. Bennett has said, in the Southern and Western portion of America, they have lost millions of acres of land because of too much use of fertilisers. Our people must be taught the proper use of fertilisers. Don't think our farmers are ignorant. If you go a few miles from Delhi to Haryana, you will find farmers who do not require B.D.Os. to teach them agriculture and all these things. What is happening in our country? There are as many as 130 I.A.S. who come out annually and rule our country; these men think they know everything. Our Prime Minister is guided by the 'Save India

[Shri H. P. Chatterjee]

Club" of 3 I.C.S. men. What do they know? Why not change I.A.S. into Indian Agriculture Service? Let us have technical men; let us link laboratories to fields and let us all go to villages and create proper enthusiasm.

What about price factor? I compare here U.K. and India. For India, a tonne of ammonium sulphate costs Rs. 1752 whereas in U.K. its price is only Rs. 671. In India, single superphosphate is Rs. 1519 per tonne whereas in U.K. it is Rs. 552; sulphate of potassium in India is Rs. 829 per tonne whereas in U.K. it is Rs. 629; muriate of potassium in India is Rs. 819 whereas in U.K. it is Rs. 500. Wherever you go, this is the thing that is going on.

The less said about cattle breeding the better I thought of speaking on it because they give us organic manure to the extent of 400 million tonnes of cowdung annually which we burn and which is equivalent to 60 million tonnes of firewood. Why not save this? Without this organic manure, you cannot do anything. You have destroyed the forests, and all the humus which can preserve water and mineral matter just like a blotting paper has gone. They can keep the water in storage much more than in Govindsagar.

But you have destroyed the forests. When the dams would be choked up, floods will occur hundred fold reminiscent of the times of Noah's Ark. In your vandalism, what are you doing again? You are burning all the cow dung. Why not get for the villages soft coke and electric power for their fuel. Send the electricity there and not to the cities, not for our air-conditioning and other things. Send the electricity to the villages. Let us all combine together in this. This is our duty. I belong to no party; I am an independent member, though like all independents, I am a second class Parliamentarian here; according to you I have no worth; till I belong

to a party I am happy I could catch your eye. We, independents, represent the whole of India. Let us all combine in this endeavour and carry on this thing. We must put food and agriculture above party and do all that is possible to increase the production.

Regarding the zonal thing, I support Mr. Lobo Prabhu. This zonal restriction must vanish. Let us have the courage of Mr. Kidwai. This zonal thing has become a source of corruption. Let India be one whole. Why should the paddy not go from Bengal or anywhere to Bihar? Bihar does not have the option to buy the food from anywhere nor you will supply them that. You have the bird in the cage and kill it like that; you would not be able to take charge of it in this manner. I do not mind Bengal's paddy going to Bihar or anywhere. As a matter of fact, I found this happen in my district; there is a substitute food; they use grams and other pulses during the ban period but this time they are all exported away to Maharashtra. There should be free trade throughout India. Black-market prices should be controlled. Also merchants should be controlled, but not like this. Just because the duck is laying golden eggs, you should not open its belly and kill it. Do not kill the merchants. Procurement must be there. There should be procurement from one end to another end of India; every one should have equal chances to buy. The country is one; you should not divide it.

I thank you for having given me the opportunity.

Dr. Maitreyee Basu (Darjeeling): I just want half a minute. I want to ask only one question. I am not trying to make a speech. Just one question. I would like the Food Minister, when he replies, to give a reply to this question. It was suggested by a very important Member on the Congress Bench that agriculturists



should be treated as an industry and Gandhi's Centenary should be celebrated on those lines. I would like to ask the Food Minister whether the Congress Party intends floating a joint stock company for agriculture and if so, are they going to give it to one of the big business agency houses?

Some hon. Members: No, no.

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): If she forms a co-operative society, we will make her the Managing Director.

श्री श्री ० भा० अरव (जालना) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य और कृषि मन्त्रालय की जो मांगें हैं उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। भारतीय हासिल होने के बाद अनाज अमल पर तबज्जह दी गई, इसकी अहमियत को पहचाना गया और पहली पंचवर्षीय योजना में इस पर काफी जोर दिया गया। थोड़ी बहुत उसमें हमें कामयाबी भी नसीब हुई। लेकिन इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी अहमियत को नजर अन्वाज कर दिया गया और कारखानों पर, अन्वो पर शासन ने अपना लक्ष्य केन्द्रित कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अर्न्त में हमारे प्लानिंग कमिशन वालों को अपनी गलती महसूस हुई और उन्होंने यह तय किया कि फूड के मामले में सेल्फ सफिश्येसी के लिए, ज्यादा जोर एग््रीकल्चर पर देना चाहिए। उसके बाद कुछ तबज्जह उस पर दी गई लेकिन जितनी कोशिश होगी चाहिए थी, उतनी कोशिश इस सिलसिले में हमारे शासन की तरफ से नहीं हुई। हम अपनी पंचवर्षीय योजना के दरवाजे पर खड़े हैं। देश की अनाज के मामले में जो भी हालत है वह सब की मालूम है। हम लोग फूड के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। अनाज हमारे मुल्क में कम पैसा होता है और हमारे अन्वो अन्वो है। हर साल हमारी अनाजकी

में इजाफा हो रहा है। जिस तनाबुब से मैं भावावी में इजाफा हो रहा है उस तनाबुब से हमारा अनाज नहीं बढ़ने पाता। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जनता को तकलीफ का शिकार होना पड़ रहा है। इसके लिए बहुत से सुझाव अनाइरेबल मेम्बर्स की तरफ से प्राये हैं। मैं भी बाजु बाते इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ। हम दुनिया के दूसरे मुल्को के मुकाबिले में इस मैदान में बहुत पिछड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय 1964-65 में कनाडा में फी हेक्टर 13.6 क्विंटल गेहूँ पैदा हुआ, अस्ट्रेलिया में 13.8, अर्जेन्टाइना में 18.6, अमेरिका में 17.7, नीदरलैंड्स में 47.1 और हिन्दुस्तान में 7.3 क्विंटल गेहूँ पैदा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दुस्तान एग््रीकल्चर के मामले में खुराक के मामले में दुनिया की तरक्कीवास्ता मुल्कों के मुकाबिले में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमको इन तमाम हालात को पेशेनजर रखते हुए इस खुराक की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या करना है यह सोचना चाहिए। यह कोई सियासी मसला तो नहीं हो सकता जो भी माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं चाहे वे किसी भी दल के हों वह सभी यही बात कहते हैं। लेकिन कहां तक अमल में आता है यह देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अमल में ऐसा होता नहीं है। यहां पर हम बातें करते हैं कि तमाम लोगों को मिल कर फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए लेकिन बाहर जाने के साथ ऐसा नहीं होता। यह बड़े दुख की बात है। हम अमेरिका से गेहूँ मंगते हैं, रूस से मंगते हैं। दुनिया के दरवाजों को खटखटाते हैं और भीख मांगते हैं अनाज के लिए। वह बहुत दुःख की बात है।

[की बें० ना० जाबब]

मेरी अपनी राय है कि हिन्दुस्तान में अनाज की बहुत बरबादी होती है। इन्सान का सब से बड़ा दुश्मन अगर कोई हो सकता है तो मेरी अपनी नाकिस राय में वह चूहा है और अगर हमारी फूड मिनिस्ट्री ने चूहे का प्रबन्ध कर दिया तो हमारा जो अनाज बेकार जा रहा है और जो अनाज खाया जा रहा है चूहों के जरिए से वह बर्ब जाएगा। लेकिन हमारा शासन इस मामले में कमजोर पड़ जाता है। बुनिया के तमाम शासन इस छोटे से जानवर चूहे के मुकाबले में कमजोर पड़ रहे हैं। . . . (ब्यबधान) . . . . . हां साइंटिस्ट्स भी कमजोर हो रहे हैं मिनिस्टर साहब सही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कुछ न कुछ कोशिश करनी चाहिए। अग्रिम महोदय, हिन्दुस्तान के आदमी अजीबोगरीब हैं। चूहे को पकड़ते हैं और उसे मार नहीं डालते उसे दूसरी जगह छोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि वह चूहा अपनी पैदावार बढ़ाता है। काफी निकदार में हिन्दुस्तान में चूहे हैं। इस का नतीजा यह हो रहा है कि अनाज खाने वाले इन्सान ही नहीं हैं बल्कि जानवर चूहे और दूसरे परित्ते वगैरह सभी खाते हैं जिस से अनाज की कमी महसूस हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय! हिन्दुस्तान में एपीकल्चरल रिसर्च का काम बहुत कम हुआ है। जो हो रहा है वह काबिले-तारीफ है बाज जगहों पर हो रहा है लेकिन जिस कवर इस मैदान में तहकीकात के लिए गुंजाइश है उस कवर नहीं हो रहा है। मेरी यह गुंजारिश है कि इस सिलसिले के माहरीन से मसबिरा करना चाहिये। मैं यह मानता हूँ कि हमारे यहां साइन्टिस्ट्स की कमी है लेकिन हमें कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये। मैं इस बारे में यह अर्थ कहां कि हिन्दुस्तान में बहुत से साइन्स कालेज हैं जहां बोटैनिकल डिपार्टमेंट,

बायसीपी डिपार्टमेंट, माइकालोपी डिपार्टमेंट हैं, जिनको इन चीजों की तहकीकात का काम दिया जा सकता है, अनाज के रोग और चूहों के नष्ट करने के बारे में तहकीकात का काम दिया जाये। अगर इस तरह से इन्तजाम किया जाये तो आसानी से तहकीकात का काम हो सकता है और इन कामों पर ज्यादा पैसा खर्च करने की नीवत नहीं धारियेगी।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां बेटी की नुमाइश बहुत सी जगहों पर एकबीबीशब्ज होती भी है लेकिन हर मौसम में यह मुमकिन नहीं होता है। मेरी गुंजारिश यह है कि इस किस्म की नुमाइश कम से कम जिले के मुकाम पर हर साल बकर होनी चाहिये ताकि किसानों को अच्छे बीज और नये तरीके की मर्कनाइज्ड फामिग बगैरह की मालूमता हो सके। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। इस किस्म की नुमाइशों की देखने के बाद नये तरीकों के बारे में किसान प्रतीसा करेगे उनको अपने यहां काम में लायेंगे और फिर उससे मुल्क की अनाज की पैदावार ज्यादा होगी।

तीसरी बात जिसकी तरफ आस तीर से तबज्जह दी जानी चाहिये वह यह है कि मंने प्रकमर देखा है कि किसान बीज के लिये जिला परिषद्, पंचायत दफ्तर, एपीकल्चर आफिस और सेक्रेटेरियट के बकर मारता रहता है लेकिन उस को बक्त पर बीज नहीं मिलता। जिसका नतीजा यह होता है कि वह कहीं से भी बीज लेकर भी देता है। मैं इस सिलसिले में एक मिसाल देता हूँ—अभी हाव में ईजराइल और अरबिस्तान की लड़ाई हुई, ईजराइल ने अपने यहां दो-दो, डार्ड-डार्ड, तीन-तीन मील पर एक इन्टीयूशन कायम की है जिसे हम मस्टीपरपज इन्टीयूशन कह सकते हैं। वहां पर किसानों को जिन चीजों की जरूरत होती है उदाहरणार्थ बीज, खाद, ट्रैक्टर आहिर का मसबिरा वगैरह इस तनाव चीजों को मुहैया किया जाता है। इस तरह से

झरपाइन नै किलानों के बरबाजों तक उन तमान बीजों को जिनकी किसान को जरूरत होती है पहुंचा दिया है। झरर इती तरह से ह्वारा डिपार्टमेंट, मंत्री महोदय, कुछ पहल करें तो किसानों और मुल्क पर बड़ा सहसान होगा।

एक बात धाखिर में धीर धर्ज करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करने जा रही है। मैं मराठवाड़ा से आता हूं जहां पर कोई इण्डस्ट्री नहीं, कारखाने नहीं हैं सिर्फ एग्रीकल्चर ही है। वहा की जमीन बेहतरीन जमीन है सोना उगलने वाली है जरखेज है, झरर आपने किली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इजाजत दी है और वह खोली जाने वाली है तो उसके लिये कोई बेहतरीन बैंकप्राउच हो सकती है तो वह मराठवाड़ा की जमीन ही सकती है। मिनिस्टर साहब कहने कि यह तो आपकी जाती राय है यह तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम है कि वह इसको कहां पर बनाना चाहती है। मैं आपसे यह गुजारिस करूंगा कि मराठवाड़ा पिछड़ा हुआ है इसलिय आप महाराष्ट्र के शासन पर धपना धसर इस्तेमाल करें ताकि श्रीरंगाबाद के मुकाम पर जो कि मराठवाड़े का कॅंपिटल है, यह क्विच यूनिवर्सिटी कायम हो सके।

हमारे मंत्री महोदय धीर उनके डिपार्टमेंट ने एग्रीकल्चर के सम्बन्ध मे काफी काम किया है लेकिन इन कामो को धीर ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। खास तौर से बन्धन का काम ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये ताकि वर्षा के पानी को रोका जा सके। इससे बाधोलियों के पानी की सतह ऊंची ही जावगी धीर उससे किसानों को बहुत फायदा होगा। एक सबसे बड़ा इन्सेम्प्टिब किसानों के लिये सनाज की पैदावार बढ़ाने के लिये यह हो सकता है कि भाव बांधे जाने चाहिये, उसे

ज्यादा से ज्यादा भाव दिये जाने चाहिये इसके वह सनाज की पैदावार की तरह बढ़ेगा धीर सनाज की पैदावार बढ़ेगी, झरर ऐसा नहीं किया गया तो पैदावार नहीं बढ़ेगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (मेडक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं। धर्ज के बारे में डिस्कन हो रहा है बहन सके बारे में बेहतरीन जानती हूं, लेकिन उनमें से धर्जी किली को नहीं बुलाया गया, उनको बोलने के लिये मौका देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका नाम भी है, धर्जी ध्रायेया।

Shrimati Mohinder Kaur (Patiala): I rise to support the demands of the ministry.

The cut motions tabled by the friends opposite show the gravity of the situation. It also shows that this is a subject which cuts across party lines and narrow alignments. This is a subject which is of vital importance to this country, attainment of self-sufficiency in food, and we are all concerned with it. At the recent Chief Ministers' conference, as I was reading through the conclusions, some very practical suggestions emerged, and I do hope they will not remain only on paper, but Government will implement them.

Shri P. Venkatasubbaiah (Nandyal): The treasury benches are empty, there is no minister here.

Shri M. N. Reddy (Nizamabad): The discussion is on demands for grants of the Food Ministry, and the concerned Cabinet Minister or the Minister of State is not present.

**Mr. Deputy-Speaker:** The Cabinet Minister and Minister of State were both present just now, they must have gone for tea.

**Shri M. N. Reddy:** They were present just now, but they are not present now.

**Mr. Deputy-Speaker:** I shall see that they come back soon. We should not waste time.

**The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs (Shri R. L. Chaturvedi):** They will return within five or six minutes.

**Shrimati Mohinder Kaur:** For instance, one suggestion that they have made is that a simplified, unified credit structure should be evolved in the country. The credit structure for the farmers, as you know, is a very cumbersome one. Perhaps you are aware that if a small farmer wants credit from the Government, it takes a minimum of six months to one year to get it. First you have to go to the patwari because you have to take the *khasra* number. It is almost like pledging the land to the Government, and he is given a loan against that. From the patwari, it has to be endorsed by the village level worker. From there it goes to the Tahsildar for endorsement. From the Tahsildar it goes to the Agricultural Extension Officer. From there it goes to the Block Development Officer, and from there, for final sanction for even a small credit, it has to go to the Collector. And all this takes at least six months to one year, which is a very unsatisfactory arrangement. The Chief Ministers have drawn the attention of Government to the need for a uniform, simplified credit structure in this country, and I do hope Government will take note of it.

I want to quote an instance to you. The other day I was talking to a man from my own constituency. He had applied for a small loan of Rs. 1100,

and he had not crossed the last hurdle, the final sanctioning authority, namely the Collector. He was going to and fro with his application to various people, and he had spent Rs. 300 for getting a small loan of Rs. 1100.

I do not know why there is this glaring discrimination between industrial and agricultural loans. In my own State of Punjab, small agricultural loans to the farmer are made available at a rate of interest varying from 9 to 12 per cent, while for industrial development, loans are made available at a rate of 3 per cent, simple interest. I do not now why this glaring discrimination is made between farmers and industrialists. I want to come back to irrigation. In this country we want to go in for high yielding varieties. Irrigation is an important factor. Without irrigation we cannot go for this programme of high yielding varieties in a big way. We spent Rs. 700 crores on minor irrigation in the last three plans. I strongly urge that the present budget provision under this head should be increased by fifty per cent. Unless we give more money and provide more facilities to the farmers by way of minor irrigation projects, we cannot go in for this programme. You are aware that these high yielding varieties could be grown only on wet land because a lot of fertiliser has to be used. I have also said before that loans should be made available to the farmers owning two or three acres of lands.

There are certain impediments which are the causes of stagnation of agriculture in this country. Time and again I have spoken on the same subject of land reforms. A number of other people also have spoken but it has been a cry in the wilderness. Any person who is in possession of land beyond a ceiling which the law has imposed has a particular attitude; his effort will be to take out as much as he can out of that land without putting something back into that land.

Unless there is proper inputs, land will become unproductive. This is one important cause of agricultural stagnation. I shall substantiate my argument. I have spoken before in this House and I want to draw the attention of this hon House to a report submitted by Mr. Wolf Ladejinsky who came to India as a Ford Foundation consultant and he went to the districts in India where we have these package programmes and made a through study of this problem and he came to the conclusion that one of the major impediments, one of the causes responsible for stagnation in agriculture was the implementation of land reforms. When I say so, I also know that there is something which we ought to do. We should stop the fragmentation of holdings. We have no law to prevent fragmentation at a certain stage; so it keeps on going and the holdings are getting smaller and smaller and at a certain point it becomes uneconomic. If we do not pay proper attention to this problem, a time will come when the entire agricultural land in the country would become uneconomic holding. Serious thought should be given to this problem. Secondly, about the speedy implementation of the land reform policy, I have to say this. They say give the land to the landless. Agriculture is also like any other profession. You should have the aptitude, the feel for the land. Every landless labourer cannot become an agriculturist. You cannot just take a thousand or two thousand landless labourers and put them on the land because agriculture would not prosper unless the farmer has the aptitude and the feel for the land. What do I find when I go round, because I am connected with several voluntary organisations, is this. People are settled on the land; Government even pays them some money and allots them developed lands. After six months or so, they sell it because they do not have the understanding, the aptitude and the feel for the land. If there is surplus land, it should be distributed.

श्री राम लक्ष्मण दास : (बाराबंकी)  
झाप के पास कितनी भूमि है ?

श्रीमती मोहिन्दर कौर . मेरे अपने नाम में ?

श्री राम लक्ष्मण दास . झाप के परिवार के नाम में । यह जाल बट्टा मैं भी बहुत जानता हूँ ।

Mr. Deputy-Speaker: You continue; ignore interventions from there

Shrimati Mohinder Kaur: What I was saying is that when surplus land is allotted to the landless, it should be an economic unit, that should be taken into account. It should not be just a couple of acres. It should be an economic unit, where a family can depend for its livelihood. It should be an economic proposition and not just a couple of acres.

The hon Member who preceded me—Shri H P Chatterjee—made certain points. I fully endorse what he said when he talked about soil conservation, and erosion of soil. I fully endorse and I fully agree with him when he talked of the zonal system. I know I am going to tread on delicate ground here. I do not know why the Government have adopted this policy of zonal system; closing the barriers. This is one country. I am not in a position to speak about other States, but speaking of my own home State, I want to tell you that this is a disastrous policy that we have adopted. I will tell you that a glut has been created in the market, there was plenty of incentive given to the farmers to grow more wheat, and the farmers in Punjab went in a big way to grow high-yielding varieties of wheat. We have fixed Rs. 70 to 85 for a quintal of wheat. What happens? We closed the borders, to Haryana, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh which are the adjacent areas to the State. What happens? There is always a glut. The Food Corporation

[Shrimati Mohinder Kaur]

is not allowed to go directly to procure the wheat in that area, and the State Government has taken the responsibility. I want to tell you that it is not a very satisfactory arrangement.

I also want to draw your attention to the fact that wheat prices have been fixed for Punjab. The price of coarse grain is much higher than that of wheat in Punjab, whether it is bajra, maize, jawar or cotton seed. Look at the price chart. It is very much higher than wheat. I am not exaggerating. What I am telling you is a mere fact. As a result of that, the wheat is being fed to cattle, as cattle-feed, because it is the lowest. I certainly feel that something ought to be done about it. I just want two or three minutes more. Sir, Something should be done about it, because, after all, this is one country, and the people across, in Bihar, Uttar Pradesh and in so many other parts of the country are almost on the verge of starvation, and this is mainly because we have narrow outlook. We have closed the barriers. The barriers should be removed; we must not close the barriers. It is a very very wrong thing, and I request that serious note should be taken about it.

I will tell you another thing. About two months ago, when the Punjab Government came into the zonal system, I wrote to the Chief Minister, when the price was fixed for wheat. I hold the Chief Minister in very high esteem; he is a personal friend. He was gracious enough to reply to my letter; he took about six to seven weeks to reply to my letter. In that letter he said that he had not only to take care of the interests of the producer but the interests of the consumer also. This was his reply; it was not administrative approach. This was the reply. I do not know what it was based upon, because Punjab's economy depends on agriculture. In Punjab, 80 per cent of the people live on land; it has a village economy. Of

course, there was a time when we were proud of our industries, but as a result of the reorganisation of Punjab, all our industries went to Haryana. I wish them all luck. But the industries have gone out. There was a sum of about Rs. 500 crores capital which had been invested in the industries in Punjab; there was a great industrial development; an industrial belt was there comprising Faridabad, Sonapat and nearby areas. Secondly, on account of the Indo-Pakistan conflict also, the industrialists from the border districts of Punjab, where there were some big industries, have pulled out because of insecure conditions; and now, we only depend upon agriculture and our economy is based on agriculture. Therefore, to say that the interests of the consumer has to be taken into account is not a logical argument. I am afraid I do not know what is meant by it.

I was reading with great interest the proceedings of the Chief Ministers' conference which has just ended in Delhi. It was reported in the press that the Chief Minister of Himachal Pradesh Dr. Y. S. Parmar, said that if this attitude persists, they would cut down all the forests and start going in for food production in a big way because they have no other option. He also said that the result will be soil erosion and Bhakra into which we have sunk crores and crores, will be silted. This is a narrow minded policy. I do feel that something ought to be done and the whole policy ought to be reviewed.

After devaluation, the cost of fertilisers has gone up by 25 per cent and at the same time, Government have withdrawn the subsidy on fertilisers. When we talk of practical approach to attain self-sufficiency by 1971, these are the practical things which should be looked into. The whole policy should be reviewed and the price of fertilisers should be brought down.

भी भोजन का : (जननगर) : का सहकारिता और सामुदायिक विकास मंत्रालय की जो बजट माने प्रस्तुत की गयी हैं उन का पूर्वतः विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की कुछ इसकी दुष्की गलतियों का उस में समावेश है। बल्कि इसलिए कि आज जो स्थिति देश की है उसमें पूरी कृषि नीति इस आधार पर बनाई जा रही है जिससे जो खेती में काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं, वे जमीन के मालिक न रहें, धीरे धीरे उन के हाथ से जमीन सिमट कर कुछ एक हाथों में इकट्ठी की जाये।

यह जो स्थिति है, वह बिलायत में कुछ हद तक चल सकी है, दुनिया को नूट कर उस ने कुछ हद तक इस को चलाया है और दुनिया की बीनत उस ने इकट्ठी की है। यह नीति अमरीका में भी चल सकती है। लेकिन जो स्थिति जापान की है, उस स्थिति में यह नीति वहाँ भी नहीं चल सकती है और जो सब से प्रतिक्रियाशील नेतृत्व में चलने वाला ताइवान है उस में भी यह नीति नहीं चल सकती है।

[SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA in the Chair].

मैं अभी बाद की बातों में जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जंसी जमीन आबादी वाला देश इस रास्ते पर चलेगा तो जो हमेशा ही हमें खायापान के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले सिंचाई मंत्री ने कहा था कि पिछले दस बरसों में चौदह सौ करोड़ रुपये की राशि सिंचाई पर खर्च हुई है। यह भी यहाँ पर कहा गया है कि उसी अवधि में सौलह सौ करोड़ रुपये का आयाज अमरीका से तथा विदेशों से मंगाय गया है और यह राशि विदेशी मुद्रा के रूप में देनी पड़ी है। हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि लगातार हम घाटे में चल रहे हैं। हमारे बिल मंत्री रोना रोते हैं कि हमारे देश में एक लाख इनफ्लेशन भी है और डिफ्लेशन

1366 (A) L&D—9.

भी है। दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। महंगाई भी बढ़ रही है और कई भागों में प्रतिउत्पादन की समस्या पैदा हो गई है क्योंकि चीजों की बिक्री भी नहीं हो रही है। कुछ कपड़े की मिल इस कारण से बन्द हो रही हैं। चूँकि कपड़ा नहीं बिक रहा है इस वास्ते यह नीबत पैदा हुई है। यह स्वाभाविक भी है। हमारे देश की 75 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है। अगर उसके पास जमीन नहीं है, अगर घर में गल्ला नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है तो कारखाने में बैयार माल बिक नहीं सकता है। इसलिए कमी चीनी का संकट पैदा हो जाता है, कमी कपड़े का संकट पैदा हो जाता है और कमी दूसरा माल न बिक सकने के कारण संकट पैदा हो जाता है। एक तरफ मिल मालिक दाम बढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ नय शक्ति के लगातार गिरते रहने की वजह से उनके माल, की बिक्री नहीं होती है। इस से हमारी तरह जो सर्व व्यवस्था है वह संकट में पड़ गई है और बढ़ती जा रही है। माल बिक नहीं रहा है और कारखाने एक साथ बन्द हो रहे हैं। दूसरी तरफ इसी सामान के बगैर लोग मुहताज हैं, नंगे हैं, भूख हैं, उनके पास दवा दारू के साधन नहीं हैं।

सरकार विदेशों से ट्रैक्टर मंगाने की बात सोच रही है, सोवियत सभ से और रूसी-कॉलोकाकिया से ट्रैक्टर मंगाने की बात सोच रही है। वह सोचती है कि कुछ राजाओं और राजियों के जो खेत हैं उन में ट्रैक्टरों से खेती हो। इन ट्रैक्टरों की सहायता से एक मिनट के लिए मान लो कि खेती की पैदावार बढ़ जायगी है तो क्या इस देश की बेकार और जमीन के लिए भूखी जनता को काम मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी? जनता के हाथ से जमीन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वे छिनते जा रहे हैं। राजा और राजिया यह स्वप्न देख रही हैं कि जमीन की टुकड़े बनवी नहीं हो, जमीन की चकले बनवी हो। हजाराँ छोटे-छोटे ट्रैक्टर से करके बड़-बड़ जमीनों के

### [श्री मोरेश्वर झा]

बकले बनाये। बाकी जो बहुसंख्यक आबादी है वह बेकार होती चली जाए। हमारे देश में भुखड़ों की, बिखमनों की, बकारों की एक जमायत बनती जा रही है। उस जमायत की क्या हालत होगी। देश के बाजार की क्या हालत होगी। अब यह जमाना नहीं है जबकि वासकोडेगामा और कोलम्बस विदेशों में जा कर बाजारों का पता लगा लेते थे। आज हिन्दुस्तान के लिए दुनिया का बाजार भी खुला हुआ नहीं है। जहाँ तक मन्दरूनी बाजार की हालत है, वह भी क्रय शक्ति के अभाव में सिक्ड़ता जा रहा है। वह बड़े नहीं रहा है। देश के करोड़पतियों को यह भ्रम भी नहीं है कि विदेशों में बाजार ब टूड़ ताकि माल की देश से और विदेशों में बिक्री हो सके। अरब देशों के बाजार को ढ़ुंने की उन को चिन्ता नहीं है। उन को चिन्ता यही है कि मालिक अमरीका जो है वह किस तरह में खुश रह सकता है और उस को उस तरह से खुश रखने की कोशिश की जाती है। इसी नीति को वे अपने जरिये तथा अपने भ्रमबारी के जरिये बना रहे हैं।

उस तरह के हमारे भाई जब भूमि सुधार की बात पेश होती है तो कहते हैं कि समाजवाद की ओर हम देश को ले जा रहे हैं। ऐसा कह कर वे हमें अपने भ्रम में और धोखे में डालना चाहते हैं। लेकिन हम धोखे में पाने वाले नहीं हैं; इस सरकार से समाजवाद की कोई आशा हमें नहीं है। हम चाहते हैं कि पूँजीवाद ही चलना है तो इस को आप राष्ट्रीय नीति के आधार पर चलाये, इन तरह में चलाये ताकि छोटे और मझोले लोगों की व्यक्तिगत पूँजी की रक्षा हो सके। दाहिनी ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के पुजारी हैं, व्यक्तिगत सम्पत्ति की पवित्रता की बात वे करते हैं लेकिन उन को देखना चाहिये कि आज हमारे देश के सम-भग सात आठ करोड़ परिवार जो खेती पर निर्भर रहते थे या आधा मुर्दा बन कर

रहते थे, जो मेहनत करते थे, अब व्यक्तिगत सम्पत्ति उन के पास नहीं रह गई है, वे बेजमीन हो गए हैं, उन की व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा आप करना नहीं चाहते हैं। आप तो यही चाहते हैं कि वे सम्पत्ति से हाथ धो बैठें। और राजा और रानियों को, टाटाज और बिड़लाज को वह मिल जाए, यही व्यक्तिगत सम्पत्ति के पुजारी हिन्दुस्तान में रह जायें, उन्हीं के पास मारी सम्पत्ति केन्द्रित हो जाए। जब इन गरीब लोगों से जमीन छीनी जाए, कुदाली छीनी जाए, और वे इस बेदखली का विरोध करने के लिए खड़े हो जायें, अपने घरों की रक्षा के लिये खड़े हो जायें, अपनी फसलों की रक्षा के लिए खड़े हो जायें तो हमारे होते हैं कि नक्सलबादी हो गया। तब आप को बुखार आ जाता है। यह जो देश का नेतृत्व करने वाले शासक दल के लोग हैं, इन को बुखार आ जाता है। तब एक भूकम्प सा आ जाता है। मैं समझता हूँ कि एक ही नीति पर पैकिंग रेडियो और हमारे चह्लाण साहब चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पैकिंग कहता है कि माओ के इशारे पर ये विद्रोही चल रहे हैं और गृह मंत्री जी कहते हैं कि आदिवासियों ने तीर कमान और धनुष बाण छीन लिये जाये। क्या इस तरह से देश को आप तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं? आप को चाहिये कि जिन के पास जमीन नहीं है उन को आप जमीन दें।

यह एक बुनियादी मबान है। यह टलने वाला नहीं है। खेत में जो मेहनत नहीं करते हैं जो खेत से दूर रहते हैं और जिस में नोक सभा के सदस्य भी हैं, बड़े-बड़े अफसर भी हैं, जो कि जमीन को देखते तक नहीं हैं। जो इस तरह से जमीन के मालिक बने बैठें उन का अग्रर नाम लिया जाता है तो शासक दल के नेताओं को बुखार पाने लग जाता है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप जापान की नकल ली करे फारमोसा की नकल तो आप करें। कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी गई थी कि अग्नी बीस करोड़



एकड़ जमीन ऐसे लोगों के पास है जो ऊपर के लोग हैं, जो जमीनदार हैं, जो खेती नहीं करते हैं। यह स्थल खाद्य मन्त्री जी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तीस एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से अधिक जालों की भूमि 8 करोड़ 20 लाख एकड़ है और दस से तीस एकड़ भूमि 11 करोड़ 70 लाख एकड़ है। जापानी पूंजीवाद एशिया का सबसे बड़ा पूंजीवाद है और उस पूंजीवाद के मुताबिक भी अगर आप उस की नकल करना चाहते हैं तो बीस करोड़ एकड़ जमीन अभी लेकर आप जमीन वालों को दे सकते हैं, उन को दे सकते हैं जो शान्ति दिन मेहनत करते हैं, सूखा पड़ जाए तो भी पड़ो से पानी भर कर जा कर मिचाई करते हैं, कुदाली आदि लेकर अपने खेतों को ठीक ठाक करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन उन में अधिकांश की अपनी जमीन नहीं है। जहाँ कान नहीं है, वहाँ मोना है और जहाँ कान है, वहाँ सोना नहीं है। आज हमारे देश में जमीन के मालिक वे हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, जो खेत पर नहीं जाते हैं और जो ट्रैक्टरों की मारा करते हैं। हम चेकोस्लोवाकिया और अन्य देशों से ट्रैक्टर मगाने पर रुपया खर्च किया जा रहा है, जब कि हमारी कुदाली और खुरपी बेकार पड़ी हुई हैं। जब कि हमारे हाथ बेकार पड़े हुए हैं।

16 hrs.

आज आवश्यकता हमें बात की है कि जमीन के मौलिक सवाल को हल किया जाए। नक्सलवादी का हाँवा खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। हमारा इंडियन पीपल कोड अग्रेजों का बनाया हुआ है, लेकिन उस के अनुसार भी किसान को यह अधिकार है कि अगर कोई उस की सम्पत्ति या खेत पर हमला करे, कोई उस की बेदखली करने के लिए जाये, तो वह साठी ले कर उस का मुकाबला कर सकता है। वह नक्सलवादी से कर रहा है और समूचे हिन्दुस्तान में करेगा। हम साठी से किसान के खेत की रक्षावाली करेंगे और बेदखली का मुकाबला करेंगे। इंडियन पीपल कोड में हमें उस का अधिकार दिया है।

बिना लोगों को देश की फिक्र है, उन को इस का नेतृत्व करना चाहिए। चीन का हुस्म या माधो का हुस्म हमें इस मार्ग से डिखा नहीं सकेगा। अगर माधो हुस्म से कर धारणा, अगर वह यहाँ कदम बढ़ायेगा, तो हम तत्काल से उस का मुकाबला करेंगे, जैसा कि हम ने किया है। लेकिन हम चीन और माधो के हाँव के डर से किसान को उजड़ने नहीं देंगे, उस को बेदखल नहीं होने देंगे, खेती को बर्बाद नहीं होने देंगे।

मैं समझता हूँ कि देश का बाजार बढ़ाने के लिए ऋण शक्ति बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि पंचायतों की अदादी वाले इस देश में ट्रैक्टर मगा कर गरीब किसानों को बेदखल करने की बीमारी को न शुरू किया जाये। जब यहाँ ट्रैक्टर का जमाना आयेगा, तब हम उन का चलायेंगे। लेकिन इस समय बिदेगों से ट्रैक्टर मगा कर अपने हाथों को बेकार न करे बल्कि किसान को जमीन पर कानूनी हक दे कर उस की मदद करे।

जहाँ तक सिंचाई का सम्बन्ध है श्रीमती इन्दिरा गांधी की श्रीमती सरकार ने इस देश में उस की अहमियत को अनुभव नहीं किया है। इसी लिए सिंचाई विभाग के मंत्री को मंत्रि-मंडलीय स्तर देने की जरूरत नहीं समझी गई है। सम्भव है कि चूँकि सिंचाई मंत्रालय के राज्य-मंत्री एक विशेषज्ञ हैं इसलिए उन को मंत्रि-मंडल स्तर का मंत्री नहीं बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि उस तरफ ऐसे लोग मिल जायेंगे जिन्होंने जिन्दगी भर सिंचाई को अपनी आँखों से नहीं देखा है। अगर किसी विशेषज्ञ को मंत्रि-मंडल स्तर का मंत्री नहीं बनाया है तो ऐसे लोगों को ही बना दिया जाये।

यह सरकार खाद देगी, ट्रैक्टर देगी, चकबन्दी करेगी लेकिन पानी नहीं देगी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेगी। पानी के बगैर खाद की कोई उपयोगिता नहीं होगी और उपज नहीं बढ़ सकेगी। हमें जो रिपोर्ट

[श्री भोगेन्द्र झा]

वी गई है, उस में कहा गया है कि देश में कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास, सहकारिता, पेट्रोसियम और वित्त विभागों के कार्य में समन्वय किया जा रहा है,। लेकिन हम देखते हैं कि इन विभागों में सिंचाई विभाग को शामिल नहीं किया गया है जिस से सिंचाई के प्रति इस सरकार की उपेक्षा स्पष्ट तौर पर प्रकट हो जाती है।

बिहार सरकार बराबर इस बात पर जोर देती रही है कि केन्द्रीय सरकार या तो कोसी-गंडक योजना को ले ले, जिस से पचास लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी, और या वह उस के लिए बिहार सरकार को रुपया दे। लेकिन केन्द्रीय सरकार कहती है कि उस रुपये से हम भ्रमरीका से बाजरा मंगायेंगे, लेकिन कोसी-गंडक योजना के लिए बिहार सरकार को नहीं देंगे। हमारे देश में, गंगा-जबना की तलहटी में, कमला-कोसी की मिट्टी से फसल पैदा करने के लिए इस सरकार के पास रुपया नहीं है, जिन मोटों को वह छोटा कर के छाप रही है, वं भी नहीं है, लेकिन विदेशों से कर्जा लेने में इस को शर्म नहीं आती है, कर्जक नहीं मालूम होता है। इस सरकार ने भारत को कर्जखोरों का देश बना कर रख दिया है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है रूस से जो ट्रेक्टर मंगाए जा रहे हैं, वह भी हमारे लिए शर्म की बात है। अगर कोई बुनियादी कारखाना बनाया जाये, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। जैसे, सूरतगढ़ फ़ार्म में जो उपज बढ़ाई जा रही है, वह हमारी है। लेकिन इस प्रकार बाहर से, बाहे किसी भी देश से—स्वर्ण से या नरक से—ट्रेक्टर मंगाना बहुत बुरी बात है। जब आवश्यकता होगी, तो उन के पुजों के लिए हम कहां दोंगें ?

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि कृषि को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। सिंचाई का मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं है। उस के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत

नहीं है। मिट्टी हमारे पास है। कुदासी और हाथ हमारे हैं। हमारा अपना रुपया खर्च होगा। इस लिए सिंचाई की योजनाबद्ध चला कर हम डेढ़ दो सालों में अपनी उपज की सात फ़ीसदी कमी को पूरा कर सकते हैं। इस कमी को पूरा करना बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में रुपया न होने और खर्च में कमी का बहाना किया जाता है। एक तरफ़ सिंचाई की उपेक्षा की जाती है और दूसरी तरफ़ खाद के नाम पर भ्रमरीका से साठ-गांठ की जाती है और विदेशी कम्पनियों की खुशामद कर के उन की अपमानजनक शर्तों को मंजूर किया जाता है।

भाज खाद्यान्न के सम्बन्ध में सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। कभी कभी हमारे खाद्य मंत्रों को जब जोश भाता है, तो वह कहते हैं कि हम खाद्यान्नों का राज्य-व्यापार शुरू करेंगे। लेकिन फिर बात जहा की उठाई रह जाती है। हम जानते हैं कि इस सरकार के न चाहने के बावजूद वह दिन नजदीक आ रहा है, जब यह देश भूखों नहीं मरेगा, कंगाल नहीं रहेगा, विदेशी कर्जों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि वह खाद्यान्न की एक राष्ट्रीय नीति अपनायेगा। अगर हम लोगों के सहयोग से सम्भव नहीं हुआ, तो इन को उखाड़ फेंक कर, इन को ठंकर मार कर यह देश एक राष्ट्रीय खाद्य नीति को अपनायेगा और भ्राम्ये बढ़ेगा। वह इन लोगों के धरोसे नहीं रहेगा।

खाद्य मंत्री ने बार-बार इस सदन में यह कहा है कि बिहार सरकार हम से 4 लाख टन अनाज प्रति-मास की मांग कर रही है, लेकिन वह देना सम्भव नहीं है और हम ने सवा दो लाख टन देने का तय किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि जितना अनाज इस सरकार ने भेजने का ऐशान किया है, नवम्बर से अब तक उस में भी सवा दो लाख टन की कमी रह गई है। पून में सवा दो लाख टन जाना था, लेकिन कुछ किसान

कर 1,26,787 टन भेजा गया है। बिहार सरकार बाहरी है कि वह पूरी तरह से मुनाफा-खोरी और महंगाई को रोकें, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने जितना भनाज देने का वादा किया है जो बहुत नाकाफी है वह उस को भी देने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार को पर ऐसान कर के भ्रष्टाचारों में छपवा कर और इस सदन में कह कर भी प्रभाव में कमी कर देती है। इस लिए उस के प्रति विरोध का वातावरण पैदा हो रहा है।

बिहार की गैर-नापसो सरकार के प्रति केन्द्रीय सरकार का क्या रुख है वह इस बात से पता चलता है कि यद्यपि पिछले साल इमने बिहार सरकार को दो करोड़ रुपये का अनुदान दिया था, जबकि हालत इतनी खराब नहीं थी। लेकिन इस वर्ष उतना अनुदान देने में भी इन्कार कर दिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से यह मांग की जाती है कि गडक-कोसी योजना को चालू करने के लिए उसको कम से कम पंद्रह करोड़ रुपये का कर्जा दिया जाय, लेकिन केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। इस का परिणाम यह होगा कि बिहार के लोग अपने महा अपनी सरकार के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की इस नीति के खिलाफ "बिहार नव्य" की ओर फिर बढ़ेंगे। आज नक्सलवादी के नाम से इस सरकार को बुझा चढ़ता है। कल अगर "बिहार नव्य" होगा, तो उस बुझा कर पार और बढ़ जायेगा। हम न भूखों मरने के लिए तैयार हैं और न कंगाल रहने के लिए तैयार हैं। बिहार में जो भ्रष्टाचार की हाकत थी, उस को देखते हुए मिल मंत्री ने यह खतरा बाहिर किया था कि वहाँ पर भूख से बहुत लोग मरे, लेकिन बिहार की नई सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचार के होते हुए भी बड़े पैमाने पर भुखमरी नहीं होने दी।

नये खाद्य मंत्री जिस तरह से आते हैं, उस को बुझिने रख कर कुछ लोगों के मन में यह धन था कि वह खेतिहर नफ़्तूरो का क्या क्या ज़्यादा करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या

ज्यादा किया है? तीसरी पंच-वर्षीय योजना में मात लाख खेत-मजदूर परिवारों के पुनर्वास की योजना थी जिन में से सरकार के अपनी भ्रष्टाचारों के मुताबिक कुल 96 हजार की लगभग धाठवे हिस्से की व्यवस्था हो सकी। इस बार भी जगजीवन राम न बड़ा जोश दिखा कर पांच वर्षों के लिए 53 हजार परिवारों के पुनर्वास के लक्ष्य रखा है। तीसरी पंच-वर्षीय योजना में 7 लाख खेत-मजदूर परिवारों के पुनर्वास की योजना थी और चौथी पंच-वर्षीय योजना में 53 हजार परिवारों के बारे में योजना बनाई गई है। यह तरकीब ही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि खेत मजदूर इस स्थिति में बैठे नहीं रहेंगे।

भ्राज देश को पूर्व पश्चिम और उत्तर की ओर से खतरा है और सबसे ज्यादा खतरा है अमरीकनों का, जो नागालैण्ड में उपद्रव करते हैं, जो काश्मीर पर हमारे अधिकार को नहीं मानते हैं जो भ्राज तक मोर्रा, दमन दीव पर हमारे कब्जे को नहीं मानते हैं। इन सब खतरों का मुकाबला केवल कुछ बड़े लोग नहीं करेयें। इन का मुकाबला करना होगा पचास करोड़ लोगों को। इसके लिए यह ध्यान-रक्षक है कि हर भ्रादमी को हर खेतिहर परिवार को जमीन मिले ताकि वह अनुभव करे कि कम से कम एक घर मेरा है, यह समूचा देश मेरा है—मेरा भी है और हमारा भी है। खासतौर से रोसा कोई भी छादमी बेचर बेखरीन न रहने पाए जो बेती पर जिन्दा रहता है, तो बेती पर मेहनत करता है।

अगर वह सरकार अब भी इस बुनियादी नीति को अपनाए तो मैं इस मंत्रालय की भागी का समर्थन करूंगा, वरना मैं इस सदन से ब्राह्मण करूंगा कि इस मंत्रालय की भांगों को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया जायें। उन का पूरी तरह से विरोध किया जायें। उस तरफ के जो सदस्य पहले भ्रालोचना कर के ब्राह्मण में समर्थन कर गए हैं वे उन से भी यह ब्राह्मण करूंगा कि वे भी इस विरोध में शामिल होने की हिम्मत करें।

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anasahb Shinde): Madam Chairman, I am thankful to you for allowing me to intervene in this debate. A number of hon. Members have participated in this debate. About 13 speakers have preceded me and a number of useful suggestions have been made from all sides of the House.

I must say that the tone of the debate and the sincerity with which the Members have spoken has really impressed me. I may not agree with all the views expressed by the Members. But I must say that from all sides of the House a concern has been expressed about our agricultural production and a number of useful suggestions have been made in this regard.

Before I go into some of the major issues raised in this debate, I would like to refer to some of the suggestions and points raised by the Members. Shri Yajna Datt Sharma—I think he is not here—raised a very important point that food problem, agricultural problem, should be treated as a national problem and that it should be treated above party politics. I think, he has expressed the true sentiments of this House as well as of the whole country. I am thankful to him for saying this. I wish party differences do not come in solving our food problem and agricultural problem.

Then, Shri Randhir Singh—he is also not here—made a suggestion about the crop insurance. This subject is being debated for quite some time. I may inform the House that some active steps have recently been taken in this regard. A Bill has been drafted and has been circulated to State Governments and as soon as the comments and the observations of the State Governments are available, we shall introduce the Bill in this House. We are very anxious that, if possible, the Bill is introduced and passed in the current session of Parliament.

An Hon. Member: If possible.

Shri Anasahb Shinde: Once we introduced the Bill we shall be in the hands of the hon. Members.

Shri Ram Kishan made a number of valid points in his speech. He referred to self-sufficiency, price policy and other things. He raised one very important point that agriculture should be treated as an industry. I appreciate his sincerity in giving importance to agriculture. The thinking of the Government also on this point has been on similar lines. Unless we look into the economics of agriculture, unless we give adequate importance to price policy that is to be followed in regard to agricultural commodities, I do not think it will be possible for us to solve the problem of agricultural production. I very much appreciate the suggestion made by Shri Ram Kishan in this regard.

Shri H. P. Chatterjee, a very senior Member of this House he has a lot of experience; I have all respect for him—spoke with some feeling and he referred to soil and water conservation. I know this is of great importance because unless we conserve our soil, unless afforestation measures are taken, I do not think it would be possible for us to have an integrated development of agriculture. Soil conservation and afforestation occupy a pivotal position in the development of agriculture. I may say for the information of Shri Chatterjee that during the Third Five Year Plan, we had tried to have soil conservation and afforestation on about 10 million acres under the State Plan and about 7 lakh acres under Central Plan. Similarly, about reclamation of ravines, about 36,000 acres of land were reclaimed in the ravines and about 100,000 acres of alkaline land had also been reclaimed. 16 million acres of dry lands have been brought under conservation farming measures, and for the coming years, we are having a still larger plan for soil conservation.

Mr. Chatterjee also referred to the Indian Agricultural Service. I think, he made a very important point about this Government have realised the importance of this because unless agricultural services are raised to the level of the other services unless they are given due importance in our administrative set-up, it will not be possible for us to have the proper status of agriculture recognised in our national life. That is why, the Government of India has taken the decision to form an Indian Agricultural Service and active steps are being taken to implement this decision.

I was glad to find that a number of members referred to the high-yielding varieties programme; a number of suggestions were made and a number of words appreciating the programme were said on the floor of this House. But some members also expressed some doubts about this programme. Particularly, Shri Sharma expressed some doubts about this programme. I wish to dwell on this subject at length, but before going to that subject, I would like to mention this.

The last two years were the most difficult years from the point of view of agriculture. If I may say so, even the notorious Bengal Famine year pales into insignificance if we take into consideration the calamitous effect the last year's drought had on our agricultural production. I was just looking into the figures of production that we had in 1940-41 and 1941-42, i.e., just before the Bengal Famine; there, the fall in production was 14 lakh tonnes. But, if the similar production figures of Bihar are looked into, we will find that there has been a steep fall in production; from 75 lakh tonnes in 1964-65 the production in Bihar came down to 69 lakh tonnes in 1965-66, and again from 69 lakh tonnes, it came down to 45 lakh tonnes in 1966-67. What a steep fall! It is much more than what we had during the Bengal Famine year. Though we had such a difficult year, hon. members will appreciate that our people faced

the hard situation, the difficult situation, very courageously. All the State Governments—Bihar, U.P., M.P. and all other State Governments—were very generously helped by the Centre. An hon. Member raised a point about the assistance rendered to Bihar. May I say for the information of the hon. Member that the largest amount that has been disbursed was disbursed to assist Bihar in fighting the drought conditions, in helping Bihar in their agricultural production programmes. For instance, during the last year, and during the last few months, the total amount that has been given to Bihar is about Rs 67 crores; for Gujarat, it is Rs 44 crores; for Madhya Pradesh, it is Rs 29 crores; for Rajasthan, it is Rs 20 crores; for West Bengal it is Rs 12 crores; for Uttar Pradesh, it is Rs 7 crores. This will indicate to what extent the Centre has gone to assist the State Governments in fighting the drought conditions. But the more important point was the response of the people. Though the times were very difficult, though we were passing through a very difficult time, the way in which our people faced the difficulty should be appreciated. I must say that the morale of the people either in Bihar or in any other drought-affected area, was very high, though considerable human distress was there, our cattle wealth also suffered; even then, our people did not lose the confidence. They responded well to the call of the State Governments as well as to the call of the Centre and they fought this danger very bravely. Our rural community, our farmers in the drought-affected areas, really deserve to be congratulated on facing such a serious crisis very bravely and courageously.

Irrigation, seed, credit, fertiliser, agricultural machinery, plant protection measures, marketing, storage, incentive price—all these factors have an important bearing on agricultural production. But the most important of all these factors is the human factor, the human material. I must say

[Shri Annasahib Shinde]

that amongst many countries we have the finest human material in our rural community.

Shri Inder J. Malhotra (Jammu): Specially farmers.

Shri Annasahib Shinde: Yes. Our farmers are not only intelligent and hard-working but they respond extremely well to new scientific ideas. That has been the experience in the last few years.

I was recently reading a book on agriculture in UK and I found that though we consider UK as one of the advanced countries of the world, even now there are farmers there who do not use chemical fertilisers at all and many of them do not know modern techniques. All the world over, it is our experience that transformation from traditional agriculture to modern agriculture is a long process. But if we look at the development in our country in the last few years, we find that our people are responding to new ideas so well that one really fails to understand how is it that they are responding so well. For instance, I may take the use of fertilisers. A number of Members referred to the importance and use of fertilisers, chemical fertilisers.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur): First water, then fertiliser.

Shri Annasahib Shinde: I am coming to water too. I know the hon. Member is very anxious about irrigation. I entirely agree with the sentiments expressed by hon. Members on the floor of the House that minor, medium and major irrigation, all these need to be emphasised and we should accord high priority to these programmes.

Shri Madrika Singh (Aurangabad): That is the basis of the whole thing.

Shri Annasahib Shinde: About 12.8 million acres have been benefited by minor irrigation during the Third Five Year Plan.

Shri Pileo Mody (Godhra): During the First Five Year Plan?

Shri Annasahib Shinde: In the Third Plan period alone. The increasing importance we are attaching to minor irrigation can be seen from the fact that in 1966-67, we brought under minor irrigation alone 3.4 million acres. For 1967-68, we have an ambitious plan, and outlay to the tune of Rs. 102 crores has been provided.

Shri Pileo Mody: What about water-logging?

Shri Annasahib Shinde: A number of things are there. He should allow me to proceed.

श्री बोलेश्वर झा : इन 20 वर्षों में बिहार में माइनर इरिगेशन पर कितना खर्च हुआ और वह इन सूखे में कितना काम आया ।

Shri Annasahib Shinde: I have information with me. I am prepared to pass on the details to him.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): There is one thing. Minor irrigation potential created is not serving its purpose. They have almost dried up.

Shri Annasahib Shinde: Some wastage is necessarily involved. Some wells dry up. But the wastage is not very high. The utility of minor irrigation has been accepted by all in this House as well as outside and I do not think we should say anything against this programme.

Shri Shao Narain (Basti): It is the best scheme.

Shri Pileo Mody: Nobody is saying anything against it.

**Shri Annasaheb Shinde:** I was referring to the response of our farmers to new ideas. I was mentioning as an instance the use of fertilisers. A few years back, in 1961-62 we hardly utilised about 2.5 lakh tonnes of nitrogenous fertiliser, 0.5 lakh tons of phosphatic fertiliser and 0.2 lakh tonne of potassic fertiliser. As against that this year we are expected to use about 13.5 lakh tonnes of nitrogenous fertiliser, 5 lakhs tonnes of phosphatic fertiliser and about 3 lakh tonnes of potassic fertiliser. By 1970-71, our plan is to use about 24 lakh tonnes of nitrogenous fertiliser, 10 lakh tonnes of phosphatic fertiliser and about 7 lakh tonnes of potassic fertiliser.

**Shri Gadlingana Gowd (Kurnool):** In spite of so much use of fertiliser, why is there so much food scarcity?

**Shri Annasaheb Shinde:** The point I was driving at was that our farmers are responding so well to new ideas whereas even in some advanced countries farmers, because of their backwardness, do not use fertiliser. But in our country the farmers are so much enlightened that the demand for fertiliser is going up.

**Shri Piloo Mody:** We all agree.

**Shri Annasaheb Shinde:** I was mentioning that the availability of fertiliser is manifold as compared to a few years ago; even as compared to last year, we are increasing availability by 50 per cent.

**Shri J. B. Kripalani (Guna):** What about the response of Government to the needs of the people?

**Shri Annasaheb Shinde:** We are trying to meet the requirements of the farmers by providing these inputs.

Some hon. Members raised the issue of price. Sometime back I had also referred to this. The Government of India have appointed the Agricultural Prices Commission to advise them in

regard to agricultural Prices. Though Government use the recommendations of the Commission, in many instances they go steps ahead. For instance, this year the Commission recommended that the procurement price of wheat for Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana and UP should be between Rs. 57.5 to Rs. 65.5 per quintal while actually the prices which have been approved and at which State Governments are procuring now are: Rajasthan Rs. 77-85...

**Shri Somaavane (Pandharpur):** Abolish that Commission.

**Shri Annasaheb Shinde:** ...Madhya Pradesh Rs. 65-77, Punjab Rs. 70-75, Haryana Rs. 70-75 and UP Rs. 80-85, all per quintal.

**Shri K. N. Tiwary (Bettiah):** So Government agree that the Commission's recommendations are not scientific and realistic.

**Shri Annasaheb Shinde:** The hon. Member may have his views on that. I was saying that the sentiment repeatedly expressed on the floor of the House that farmers should be given a very reasonable price, an incentive price, is reciprocated by Government.

**Shri Piloo Mody:** Parity price.

**Shri Narendra Singh Mahida (Anand):** Can he say the same thing about cotton?

**Shri Annasaheb Shinde:** I know there are some problems with regard to cotton. We can discuss it separately. Unfortunately, it is dealt with by another Ministry, the Commerce Ministry.

**Shri Gadlingana Gowd:** What are the rates fixed by the Commission for procuring paddy in Andhra Pradesh?

**Mr. Chairman:** Since he referred to some States, Members from other States want to know about theirs.

**Shri Annasaheb Shinde:** Paddy prices for the kharif season would be determined now for Andhra. The prices

[Shri Annasahib Shinde]

which are now being paid in Andhra are last year's prices. We will get fresh reports from the Agricultural Prices Commission; further, costs have gone up during the last one year, so we will have to take all those factors into consideration before fixing new prices.

**Shri Gadilingana Gowd:** When it was possible for you to fix for other States, why not for Andhra also?

**Shri Annasahib Shinde:** I was referring to the fact that we should really try to become self-sufficient as early as possible. The present position is not really very happy, and I quite agree with the sentiment expressed on the floor of the House that we have to import food from 12,000 miles. Even the little West Asian crisis has created difficulties in regard to the availability of food. This position, if it continues, has a lot of dangerous implications. The earlier it is ended the better. That is why the Government of India has declared its intention not to have any imports from 1870-71.

**Shri Inder J. Malhotra:** Don't raise false hopes. You have been saying the same thing so many times in the past, and every time you have failed

**Shri Annasahib Shinde:** Let us try, it is worth trying. I am not prepared to say they are false hopes. This is based on very sound assumptions, to which I am going to make reference.

The main plank in our new approach is the high yielding variety programme, use of new genetic material which we are trying to popularise among the farmers.

Sharmaji while speaking yesterday asked why should we think of importing seed from outside or getting ideas from outside? I do not think in regard to science we should have any sort of prejudice. We never enquire who invented the motor car, but we are using it in India; we never enquire who invented the radio, but

we are using it. Similarly, in the case of seeds, we should not have these outmoded ideas now. Wherever advance has been made in science, we should try to utilize it to our benefit. It is a common practice nowadays to exchange breeding materials between countries. Our young scientists are doing a really good job in this respect. I must say that our young scientists have made outstanding contributions during the last three or four years especially which deserves to be recognised by this House, and I really congratulate our young scientists for the outstanding contribution they have made in developing a number of new strains.

**An hon Member:** Many are unemployed

**Shri Annasahib Shinde:** They will be employed

Many of our members have a wrong impression that all those are hybrid. Wheat is not hybrid.

**Shri Lobo Prabhu (Udipi):** The Minister is no doubt very pleased with himself. Let him kindly endeavour to meet some of the criticism of his Ministry.

**Shri Annasahib Shinde:** Perhaps my senior colleague will reply to the other points. I have no time, otherwise I would have met all the points.

**Shri Pileo Mody:** If he intervenes in the debate, it must not be to praise the engineers, praise the farmer, praise the young scientist. We want to know about food. Soon he will be praising parliamentarians and finally the Ministry.

**Shri Annasahib Shinde:** I will try to meet some of the points raised by the hon. member. New strains of wheat, paddy, maize and bajra have been introduced recently and they have not only become very popular



but this year we have also a programme for introducing all these various improved seeds in an area of 15 million acres. Because of the popularity of the programme, States have come forward to have even bigger programmes if seeds and fertilisers could be assured. The per-acre yields which we are having as a result of the adoption of the new programme are so promising that they have opened up new possibilities. We have to see this from two angles. A large number of farmers in our country are small farmers; sixty per cent of our operational holdings are less than five acres according to a recent national sample survey. Because of the high yielding varieties most of these small holdings which we considered uneconomic previously will cease to be so because we can have 4,000—6,000 lbs yield per acre or 5,000—7,000 lbs. per acre. A small farmer had less marketable surplus and less left with him for reinvestment for improvement of land. With this new possibility, the small holder can hope to have a reasonable income and a reasonable standard of living. The hon. Members of this House should help create consciousness in the country so that this programme becomes more popular.

I wish to say something about the contribution that has been made by our scientists in developing these varieties because it must be put on record. It would not have been possible to undertake this programme without the valuable contribution made by the scientists. We could give impetus to this programme because our efforts were backed and supported by the research scientists. All are now aware of the great scientific breakthrough which has recently taken place in increasing the yield potential of our major cereals and millets. Geneticists have destroyed the barriers to high yields in wheat, rice, jowar, bajra and maize. These developments arise from the re-patterning of the architecture of these crop plants, so as to make them more efficient in the utilisation of sunlight, water and

fertiliser. The pace of progress in the exploitation of research results would be clear from the fact that it was only during the rabi of 1963 that the Mexican wheat was introduced in our country for the first time. In 1966-67, we have about a million acres of land under Mexican wheat. There is probably no parallel in the world for such a rapid progress in the assessment, testing, multiplication and spread of new varieties. In wheat our scientists have now produced several selections from the material received originally from Mexico which combine high yield with desirable grain appearance and quality. Also over 10,000 crosses have been made between the Mexican and Indian wheats and there are many new varieties on the breeders' assembly line. Seeds of some of them such as Sona 227, Sonalike, Kalyan 227 and Sharbati Sonora are under large scale multiplication now. High yielding varieties of pulses and oilseeds are also under development. An African groundnut variety has proved to be very high yielding and, last year seeds of this variety were imported from Tanganyika by the National Seeds Corporation. Outstanding varieties of pulses are now in an advanced state of testing in a programme of research initiated in 1966 with the collaboration of the US Department of Agriculture. It is hoped that varieties, agronomic practices and bacterial cultures which will help to double the average yield of major pulse crops would become available next year. Similarly, attention is being paid to cotton and other commercial crops and all-India co-ordinated research projects have been initiated by the ICAR in all the major crops.

Now, the hon. Member, Shri Lobo Prabhu while interrupting me, said that I was not trying to reply to some of his queries. I know that the hon. Member has altogether different views. I do not doubt it; he may be honestly holding those views. But I do not agree with him, and I do not think the majority of the population of this country agrees with him on land

[Shri Annasahib Shinde]

reforms (*Interruption*) He spoke about detention of big landlords. The tone of his speech was like that.

Shri Lobo Prabhu: Please refer to my words, not to my tone.

श्री राम लोबक यादव : ये बोलते हैं जो कुछ आप उसी पर प्रमल करते हैं। इनका ही फर्क है। ज्यादा फर्क नहीं है।

Shri Annasahib Shinde: I would only say to Shri Yadav that we have been insisting, requesting the State Governments that they should really, rigorously implement the land reforms. I know that Shri Yadav's party is a partner in many of the State Governments. I wish Shri Yadav prevails on the State Governments to implement the land reforms expeditiously. We will help them. If any State Government wants our assistance to implement the land reforms, we are prepared to render all the necessary assistance to the State Governments. (*Interruption*). Then, the hon. Member, Shri Lobo Prabhu, raised a point that controls are inhibiting production. He made a point that whenever controls were imposed, production had gone down. I humbly differ with him. I disagree with him, because the facts do not corroborate what he has said.

Shri Lobo Prabhu: The figures do

Shri Annasahib Shinde: For instance, in the year 1964-65, it was a year of control, and the highest production of 89 million tonnes was attained by us. It was in the year 1964-65. Had the hon. Member's contention been right, then the highest production would not have been attained in the year when we had controls in India.

Shri Lobo Prabhu: What about last year when we had no control?

Shri Annasahib Shinde: Last year's comparison cannot be taken for any

purpose, because the hon. Member knows that the last two years were the periods when large tracts of our country were affected by drought, and I do not think we should compare the drought years with normal years.

Shri Lobo Prabhu: May I intervene and say that the 1966 figures were the relevant figures?

Shri Annasahib Shinde: Controls were lifted in the year 1952-53. The hon. Member, Shri Lobo Prabhu, will kindly attend to me, because he interrupted me. In the year 1952-53, controls were lifted during Shri Kidwai's period. The index of production in 1952-53 was 101. Then, it went to 119 when there was no control it came down to 115. How can you explain it? It does not mean that simply because the controls were there, production has gone down. (*Interruption*). In fact, the main point which hon. Members over there were insisting upon is free trade. The hon. Member there stands for *laissez faire* in regard to free trade.

Shri Pillee Mody: Do you know the meaning of that word?

Shri Annasahib Shinde: I know Mr. Mody alone has the privilege of knowing the meaning of these words! But may I say, the public opinion in this country wants that for the protection of the common man, for the protection of the poor consumer, for the protection of the farmer, the Government must necessarily intervene and come to their help. (*Interruption*).

For instance, immediately after the Bengal famine, a commission was appointed to go into the causes of the famine and to suggest possible remedies to prevent further tragedy. It was pre-independence period and they were not politicians. Even that Commission suggested that the State must play a positive and vital role in the

foodgrain trade. May I read an extract from that report?

"The State should recognise its ultimate responsibility to provide enough food for all. We enunciate this here as a broad principle, the implications of which emerge from the report as a whole. In India the problem of food supply and nutrition are fundamental and must at all times be one of the primary concerns of Central, Provincial and State Governments. It is abundantly clear that a policy of *laissez faire* in the matter of food supply and distribution can lead nowhere and would probably end in catastrophe. All the resources of the Government must be brought to bear in order to achieve the end in view ..."

The Foodgrains Enquiry Committee of 1957, with which Mr. Asoka Mehta was associated also recommended that there should be a progressive socialisation of trade. Perhaps Mr. Lobo Prabhu may say that Mr. Asoka Mehta was a politician. (Interruptions).

16.47 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

Mr. Deputy-Speaker: For a fruitful debate, if there are certain points, you can ask a question. But if several members interrupt, it would be very difficult. I want to regulate it. Let us maintain the dignity of the House

Shri Annasahib Shinde: I wish to draw the attention of the hon. member to the recent report of the Foodgrains Policy Committee Dr D. R. Gadgil who is a member of the Rajya Sabha and some economists were associated with this committee which submitted its report as late as 1966. This committee also has made a recommendation which goes against the views of Shri Lobo Prabhu. I will read an extract from that report:

"...In order to achieve the basic objectives of food policy, it

is necessary for Govt increasingly to acquire a large share of the foodgrains produced in the country. It is in the light of this requirement that system of procurement and regulations affecting private trade have to be formulated and appraised Govt, it is obvious, has to strengthen its own machinery for the procurement, transport and distribution of foodgrains in surplus as well as deficit areas. It would be only natural in this context to expect of a public agency like the Food Corporation of India to play an increasingly important role in the implementation of the National Food Policy."

Therefore, public opinion as well as expert opinion differ from the views expressed by Mr Lobo Prabhu. I do not think I need advance any additional arguments in support of my contention

Shri Pileo Mody: These are opinions; not facts

Shri Lobo Prabhu: Nor figures.

Shri Annasahib Shinde: I know the views of the Swatantra Party. Though I have respect for the hon. members of that party individually, I differ from their views. I feel that a free trade policy in a country like India will land us in trouble. Sometimes the prices may go down and the farmers will suffer. Therefore, unless there is a public agency to intervene in the food trade I do not think the interests of the farmers will be protected. (Interruptions).

Mr. Deputy-Speaker: You have a right to embarrass the Government by quoting what they said in the past. Have Government no right to quote what the hon. members said? He should not get embarrassed

Shri Pileo Mody: I am not getting embarrassed. He does not meet our argument by quoting facts and figures. He is just giving the opinion of some committee.

**Shri Annasahib Shinde:** It was a committee appointed by the Government of India. I am sorry the hon. Member does not know even this.

**Shri Piloo Mody:** You stuff the committees with your own people.

**Shri Annasahib Shinde:** They are not Government people, they are eminent economists.

**Shri Piloo Mody:** They are people who share your opinion.

**Shri Annasahib Shinde:** You can make that charge

Some hon. Members referred to various other agricultural inputs. Hon. Members referred to the requirement of tractors. We are trying to lay emphasis on the programme of indigenous production of tractors in our country. We have now a number of private firms who are manufacturing tractors. Their capacity is expected to be to the tune of 30,000 tractors per year by 1970-71. Last year they produced about 7000 to 8000 tractors. This year they are expected to produce 13000 to 14000 tractors. We are thinking of importing about 10,000 tractors from outside. About 2000 tractors have already been imported and about 8000 tractors, 4000 each from Czechoslovakia and USSR, are proposed to be imported and we are negotiating for importing the same.

**Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam):** Last time they said that about 20,000 tractors are lying idle for want of spares. What happened to them?

**Shri Annasahib Shinde:** I quite appreciate what the hon. lady Member has said. We are aware of the fact that a large number of tractors in the country are lying idle for want of spares. This complaint has been voiced on the floor of the House a number of times. How we have made adequate foreign exchange available for importing spares. The users themselves can avail of the foreign exchange and established importers also can import under this. Also, in regard to this requirement, we are pre-

pared to consider, if there is any specific difficulty, the suggestions if any that may be sent to us by the State Governments.

While speaking about tractors, I would like to say one thing. A large number of small farmers cannot own bullocks. Nowadays even to own a bullock it requires a big capital. I find from some of the farm management studies that 25 to 30 per cent of the farmers do not own bullocks. Unless we make tractors available to the farmers—in what way they should be made available, whether it should be through cooperative organisations or public sector organisations is a matter of detail—we will not be able to make much progress. Our intention is to formulate a scheme whereby service stations should be established all over the country and tractors should be made available to the farmers.

**An hon. Member:** What about indigenous production of tractors?

**Shri Annasahib Shinde:** I have already said that about 30,000 tractors are expected to be produced by indigenous manufacturers by the year 1970-71. We are also contemplating to establish a public sector project for the manufacture of tractors in the horse-power range of 12 to 18

Some hon. Members referred to the need of credit. My colleague would be intervening tomorrow and he would be dealing with this point. I may say only this much, that we have a very ambitious programme to make more credit available. Last year we advanced about Rs. 414 crores by way of short-term loan. We wish to expand this programme by Rs. 100 crores more. In addition to that, this programme would be supplemented by long-term and medium-term loans from ARC and other agencies.

In the end, Sir, I would only repeat that we are trying to make our country self-sufficient in food, and if hon.

Members would really try to understand the programmes that have been formulated on the basis of good scientific approach, on the basis of a realistic assessment of availability of inputs etc., they will know that we are bound to increase our production in the coming years.

I find that Shri Malhotra is not here. He was wondering whether what we have been saying can be fulfilled. If he looks at the potentiality for production that is being built up I think he will himself feel convinced that things are changing fast. With the co-operation of the farmers and the inputs we make available, this programme of self-sufficiency by the year 1970-71 should succeed. I hope and wish that the co-operation of the House and the Members would be there to implement this programme, to make this programme successful so that our country becomes self-sufficient in the nearest possible future.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Krutinan.

Shri Ram Sewak Yadav: Sir, may I . . .

Mr. Deputy-Speaker: You keep your powder dry. I will give you a chance tomorrow. We want a balanced debate here. He has some difficulties. So, I am accommodating him.

Shri Ram Sewak Yadav: I am leaving Delhi today.

Mr. Deputy-Speaker: You will get your opportunity; you will get every minute due to you.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): The day began with explosion. Let us have all the explosions, if at all, today; let us have a peaceful day tomorrow.

Mr. Deputy-Speaker: All those who are responsible for whatever explosion has taken place, they will at least pass a sleepless night, if they have any regard for the dignity of the House.

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, डी० एम० के० का एक सदस्य पहले ही बोल चुका है और आप उस दल के दूसरे सदस्य को बुला रहे हैं। मेरी समझे में नहीं आता कि आखिर यह क्या हो रहा है।

Mr. Deputy-Speaker: I have got my own programme. You will get your opportunity tomorrow. Whatever time is allotted to your group, your group will get it.

श्री राम सेवक यादव : मुझे कल यहाँ नहीं रहना है। इसी लिए मैंने आप से बार-बार यह रिक्वेस्ट की है। हमारे दल में अभी तक कोई सदस्य नहीं बोला है।

Mr. Deputy-Speaker: He is speaking for the first time. That is No 1. Then, you get ample opportunity to speak. On food debate this would be the general approach.

Shri Ram Sewak Yadav: It is not a question of party but some adjustment.

Mr. Deputy-Speaker: Please resume your seat. There must be some discipline. In the food debate, those who sit on the back benches, those who do not contribute on policy matters but who bring their own experience before the House, I want to give them early opportunity. He is one such member. So, please resume your seat.

श्री राम सेवक यादव : मेरा निवेदन है आप इस को समय देगे या नहीं, इस बात की बहस नहीं है। बहस इस बात की है कि जब सभी दलों को एक बार अवसर दे दिया गया है, तो हमारे दल ने क्या खता की है . . .

Mr. Deputy-Speaker: Now, let us try to finish both.

श्री राम सेवक यादव : . . . कि आप उस को अवसर नहीं दे रहे हैं और दूसरे दल को दोबारा अवसर दे रहे हैं ?

**Mr. Deputy-Speaker:** All of you, excluding Swatantra, have addressed a communication that priority need not go with numbers and all that and that all should be accommodated and that on every occasion a particular party should not get the opportunity to start a debate or that a particular order should not be followed. As I have explained, if you have any difficulties, I will try to accommodate both before the other discussion starts. Now, let that Member start his speech.

**Shri Jyotirmoy Basu (Diamond Harbour):** There must be some set procedure for calling members.

**Mr. Deputy-Speaker:** The Swatantra Party and Jan Sangh have time to their credit. But I have told them that I will call them tomorrow. In particular cases, I am making an exception.

**Shri Ram Sewak Yadav:** Every party has time to its credit.

**Mr. Deputy-Speaker:** He is speaking for the first time. Let him speak first. If he finishes in ten minutes, I will give opportunity to the hon. Member also.

श्री सदन विहारी बाबूदेवी (बलरामपुर) : प्राप बाद मे श्री यादव को भी समय दे दिजिए ।

**Shri Kiruttinan (Sivaganja) Sir,** I am very thankful to you and to this hon. House for giving me this opportunity to put forward my concepts and suggestions on this elaborate subject. We all know that the problem of food and agriculture is an elaborate and important problem. During my maiden speech I have taken this subject because I am purely an agriculturist. I am proud of it, and I also have come from Ramanahapuram district, which is mostly backward in Madras State as well as in India. Sir, it is economically and socially backward but not in politics because out of 17 Assembly constituencies and three Parliamentary constituencies,

not even a single candidate of the Congress Party has come out with success.

17 hrs.

[**MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair**]

You know, Sir, Ramanahapuram is also the home district of the All India Congress Committee's President, Shri Kamaraj. The vast area of this district is filled with agriculturists but half the land only is under cultivation and that too produces a single crop. There is no proper irrigation system. Thousands of tanks, minor and major, which were built up during the period of the Pandyas, have not been properly renovated or repaired.

The human resources in my district have not been utilised properly. You may be aware of the fact that our district was once exporting these human resources to foreign countries like Ceylon, Malaya, Burma and Singapore. With these human resources those foreign countries have come to profit and they have economically improved. But I am very sorry to state that under our Government now they are importing these human resources from those foreign countries and they have been kept idle, and these precious resources are labelled as Burma repatriates and Ceylon repatriates. This is the condition in my district, Sir. So, I request the hon. Food Minister to take acute and urgent steps to implement certain important schemes in our district. If that is done, we can produce a lot of foodgrains for this country.

As far as the food problem is concerned the situation in our country continues to be more critical. Our Food Minister has also pointed out recently

**Shri Narendra Singh Mahida:** On a point of order, Sir. During the Third Lok Sabha the then hon. Speaker had requested hon. Members not to approach the Chair. I have been noticing since the inception of the Fourth

Lok Sabha that hon. Members approach the Chair every now and then to know about their position.

Shri S. Kandappan (Mettur): He is making a maiden speech.

Mr. Speaker: He is not talking about the speech.

Shri Narendra Singh Mahida: I want a ruling on that. Hon. Members should not approach the Chair.

Mr. Speaker: I have said not once but twice in this House that if hon. Members come to the Chair I am not able to attend to the people who are speaking. I am expected to watch the proceedings and what they say and all that. I have repeatedly said on the floor of the House that hon. Members should not approach the Chair but should leave the paper with the Secretary so that it would be passed on to me. It is very embarrassing when they come. But when they come, if I say, "No, please go away", it will be rude and crude. I hope, hon. Members, including hon. Ministers, will maintain that they do not come directly to the Chair. I entirely agree with you.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): A point of order cannot be raised in a vacuum and take away the time of the Speaker

Shri Jyotirmoy Bera: The hon. Deputy-Speaker has called two people from other parties or even more but he has not bothered to call even one of our speakers. What is the remedy for that if we leave a chit on the Table?

Mr. Speaker: We will give you time tomorrow. Shri Nayanar need not worry.

श्री जार्ज करमंडीस (बम्बई दक्षिण) :  
 बम्बई महोदय, सदन में एक भी बंगी नहीं,  
 उपबन्धी नहीं, कोई भी नहीं है ।  
 1306 (A) L&D—10.

Mr. Speaker: There is a Minister of State. He is so lean that you do not consider him as Food Minister.

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri D. Ering): No, Sir; I am here.

श्री राजसेवक पादव :  
 बम्बई महोदय,  
 बम्बई में यह मंत्री लॉग ब्यादा बोलते नहीं  
 तां कोई यह जानता नहीं । इसलिए यह मांघे  
 पर लिखावा ने तो ब्यादा बम्बई हो ।

Shri Kiruttinan: The hon. Food Minister has recently announced that there will be a serious break-down in the supply of foodgrains from the Centre to the States during the last three months of the current year. By the end of September, the Centre would thus have in all 1.6 million tonnes of foodgrains for supply to the States as against 2.85 million tonnes of foodgrains required to fulfil its commitments.

The production of foodgrains also during the year 1966-67 is estimated at about 76 million tonnes. But it is very low production when it is compared with the peak production of 89 million tonnes in the year 1964-65 and somewhat better than 72.3 million tonnes in the year 1965-66. All this makes us feel that the outlook on the food front and on the agricultural front is rather grim. During the First and the Second Five Year Plan periods, the total outlay on agriculture, irrigation and community development amounted to Rs. 1351 crores and during the Third Plan period the outlay was to the tune of Rs. 1718 crores. It is rather a sad commentary on the planning system that even after our three Five Year Plans, our agriculture has come to a position where our average annual production during the Third Plan is less than what it was in the Second Plan period.

In our country, one hectare of land gives about 1500 kgs. of rice whereas

[Shri Kiruttinan]

in Japan it gives 4900 kgs. and in U.A.R. it gives 5000 kgs. Similarly, we get about 780 kgs. of wheat as compared to 2450 kgs in U.A.R. and 3550 kgs in West Germany

Now, the important question is why there is a stagnation in our agricultural production. The first and foremost reason is the well-known extreme poverty of a large number of small farmers in our country. That type of families constitute 80 per cent of our rural population. There is no doubt that this extreme poverty has about as a result of their being neglected by the Government for a long time. Firstly, the British Government neglected them. That at least is understandable. But what a wonder it is, I am sorry to state, that our own Government, the so-called democratic socialist Government, is also totally neglecting those poor farmers. Because of this neglect, our farmers have not received the necessary protection. So, there is less production and there is food shortage in our country.

To meet the shortage of food, during the past few years, our Government have been importing sizeable quantities of foodgrains for which valuable foreign exchange is utilised. Admittedly, imports cannot be continued indefinitely in view of the tight foreign exchange position. Efforts are, therefore, to be made to produce more food wherever possible. For this, the important needs of the farmers should be fulfilled. The first one is the need of tools with which he can improve his agriculture. For this, the Government should supply tractors and bulldozers at a cheaper rate. I want to know from the Minister whether the Government is contemplating any such scheme for this purpose.

The second thing is the timely supply of chemical fertilisers in sufficient quantities to farmers according to their requirements. The true role and

status of fertilisers in the agricultural process is far more widely understood in India today than that was ten years ago. The intake of fertilisers per block increased from 1315 quintals in 1952-53 to 5273 quintals in 1965-66. In 1966-67, it is estimated that the country is likely to have used 8 lakh tonnes of nitrogen, 3 lakh tonnes of phosphate and 1,30,000 tonnes of potash. That too did not cover full requirements. But the likely demand during 1967-68 is estimated to be 13,50,000 tonnes of nitrogen, 5 lakh tonnes of phosphate and 3 lakh tonnes of potash. It is to be doubted I doubt how the Government is going to meet this demand. Anyway, timely supply is essential. The Government has also proposed to increase the price of fertilisers. Having the procurement policy and having fixed the price of foodgrains, I cannot understand how dare the Central Government to increase the price of fertiliser. I request the hon. Minister that the price of fertiliser should not be increased. As far as Tamilzhagam is concerned, I want to stress to the Central Government that 75 per cent of the Neyveli fertiliser production should be allocated to our State. I expect a specific reply to this point.

The next important one is the supply of high-yielding variety of seeds to the farmers. The fourth one is the credit facilities. You may have a very impressive set of figures to show that so many crores of rupees have been distributed among the farmers. But if you go into the villages and look into the needs of the really small and poor farmers, you will find that it is on very rare occasions that these men get any sizeable credit. Even where credit is available through co-operative societies and panchayat unions, it is an unfortunate fact that the richer and the influential men in the area manage to get the credits. If I can openly put it, Sir, the credit societies are the financial institutions of the



Congress "Pramukhs" for their election purposes. Benami loans have been raised. Misappropriation of funds from the societies are increasing. This is what I would like to mention about co-operative societies. So far as the co-operative societies are concerned, the loopholes in the legal aspects should be tightened up and necessary action should be taken to tap the credits to the poor farmers without any difficulty.

Further, I would like to submit, Sir, that there is no use giving loans which he has got to return after some days with interest. There is no use of giving them short-term loans. Long-term credits should be given. The Central Government should not hesitate and should advise the Reserve Bank and other commercial banks to give long term loans to the farmers. More funds should be allocated from the Central Government.

It is also essential to set up certain industries in rural areas, so that they can earn some extra money and supplement their income.

Above all, to gear up the agricultural production I would submit that irrigation is very very essential. Without water, no one can produce anything even with all the other facilities such as tractors, chemical fertilisers, better seeds and cheap credit. Sufficient attention should, therefore, be given to this subject. Dr. Khosla, Governor of Orissa, also regretted that, though agriculture and food production are being given the highest priority, irrigation has been neglected. This has resulted from imbalanced and uncoordinated planning. He felt that in the context of acute food shortage and famine conditions all over India, India's prime need of the hour is more water for irrigation. Our Union Minister of State for Education, Mr. Bhagwat Jha Azad, has also recently said:

"To tide over the food problem, nothing much was required. If adequate irrigation facilities were

provided, the country could be self-sufficient in food. But the talk of irrigation was given less consideration than the proposal for fertiliser factories."

So, Sir, the amount allocated for irrigation is insufficient and the hon. Minister should look into this matter carefully.

Sir, I want to say something about community development programmes. The basic objective of the community development programme has been to generate community participation to solve the problems of our villages. To what extent has this been achieved? How many people are really aware of the colossal national effort to modernize the whole range of our rural life? How many have taken advantage of this effort? Who are the people influenced most by this programme? What progress have our villages made in communication facilities and institutional developments? Has the Panchayat Raj taken roots in the political consciousness of the common villager?

In the context of the grave food situation, has the community development programme contributed in any way to set up food production? Has it been of any help to the farmers? The hon. Food Minister should answer all these questions.

Now, I want to say something about State trading in foodgrains. Though I am in favour of State trading, unfortunately, I am unable to support the State trading under the Congress Government. According to the Audit Report, every year, State trading has given a loss account. The total loss during 1962-63 was Rs. 32.57 crores and that in 1963-64 was Rs. 33.8 crores. The Ministry gives several reasons for this. The first one is subsidy for foodgrains, and the second one is loss in transit and in storage, and the third one is loss due to theft.

[Shri Kiruttinan]

From the report of the Public Accounts Committee the quantity of foodgrains lost in transit and in storage and due to theft etc. was 42,649 tonnes in 1962-63 and 29,439 tonnes in 1963-64.

In 1963, the Ministry had stated that the amount of foodgrains damaged and rendered unfit for human consumption was 7430 tonnes worth about Rs. 22 lakhs. Up to October, 1965, the loss in transit only, according to the report of the Public Accounts Committee, has amounted to Rs. 22.54 lakhs. While the country is faced with shortage of foodgrains, a very substantial quantity of foodgrains was rendered unfit for human consumption and wasted. This is burning the heart of the people who deserve human sympathy. So, such wastages should be avoided.

Further, Sir, I understand—I do not know whether it is true or not—that the Food Corporation of India, now in Madras, is going to be shifted to Delhi or some other town in the north. Madras is also within this country

Shri Umanath (Pudukkottai): Not Kerala alone, but Madras also.

Shri Kiruttinan: If there is any such proposal, I should like to submit that it should be scrapped. Let Government think of shifting some other head offices from Delhi to Madras. Let them render justice and try to win the heart of the people of Tamil Nad.

श्रीमती लक्ष्मीबाई (मंडक) : छद्मपत्र महोदय, आज खाद्य समस्या को सम्बन्ध में वहाँ पर बहुत कुछ कहा गया है। सब बोलते हैं कि रूढ़िवादी समस्या है अगर

करते बहुत कम हैं। मिनिस्ट्री वाले सब बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, रिपोर्ट्स लेते हैं लेकिन करने की हिम्मत नहीं करते हैं। हमारे मिनिस्टर साहब जगजीवन राम हैं—जिनका जगजीवन नाम है—पता नहीं क्या करते हैं, इन को बड़ा सलोक हो जाना चाहिये।

सब कहते हैं कि जमीन में ज्यादा उगाओ, इरिगेशन का काम बढ़ रहा है, दूसरी सुविधाये बढ़ रही हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि बीमारी फिर भी बढ़ती जा रही है। दूसरे मुक्त जिनना पंदा करते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद दूसरों का भी बे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरा ही नहीं पड़ता। दूसरे मुक्त जनसंख्या में कम हो रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे मुक्तों के लोग भाष हमारे पास आ रहे हैं, रोख रगून से, बर्मा से, सिंगपुर से हजारों लोग भाग भाग कर यहाँ आ रहे हैं, पूरी दुनिया में से तीस-तीस हजार लोग इन्डुस्तान में आते हैं, पोपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि उसका असर जमीन पर भी बढ़ रहा है। हर स्टेट में एकमपैशन हो रहा है, कल्टीवेशन लैंड को काटा जा रहा है, मेरे पास आंकड़े हैं, ऐसी 12 परसेंट जमीन कम हो गई है, अच्छी जमीन जो सैकड़ों सालों से गावों में खेती के काम आती थी वह तमाम काटी जा रही है। आप तो अध्यक्ष महोदय, बड़े किमान हैं, आप हमारे प्रांत के बारे में जानते हैं...

एक माननीय सदस्य : बड़े किसान के पास ज्यादा जमीन है।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : पत्थरों की जमीन है, पानी का इन्तजाम नहीं है, जैसी

घास लोगों के पास है, उसनी नहीं है। पीने का पानी तक वहाँ नहीं मिल रहा है। धन इन्तजाम हो रहा है। घास इसको नहीं समझेंगे कि सब लोग बड़ी जमीन नहीं रखते हैं।

हम लोग धाकड़े देख रहे हैं कि जमीन सिपाई के नीचे लाई जा रही है। हम घास के हाथ में 850 करोड़ रुपये दे रहे हैं। लेकिन उसको घास लोग ठीक से खर्च नहीं करते हैं। क्या घास कभी भी उसको ठीक से खर्च करने की जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं लेते। मैं घास से सही बात कहना चाहती हूँ। जब उधर के लोग बोलते हैं तब घास को कड़वा लगता है क्योंकि वह एग्जैजरेट करते हैं। लेकिन मैं ठीक बात कह रही हूँ इतना रुपया हम घास को देते हैं लेकिन उस में से 200 करोड़ तो घास को एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करना पड़ता है। वह किसान के पास नहीं जाता है। 800 करोड़ रुपये में से घास 550 करोड़ बाहर से फटिलाइजर लाने में खर्च कर देते हैं, धीरे 150 करोड़ सन्निडी में चले जाते हैं। यह तो घास लोगों की प्लैनिंग है। बिल्कुल बेढगी प्लैनिंग है। यहाँ पर बड़े बड़े आफिसर्स अपने मुह बन्द कर के बैठ जाते हैं। लोगों ने जाकर एप्लिकेट नहीं करते कि किस तरह से काम होना चाहिए। बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते लेकिन मिर्फ इधर उधर के कामों में मारा समय गुजार देते हैं। हम भी यहाँ बैठते हैं वह भी यहाँ बैठते हैं, लेकिन सही रूप से किसी बान को सोचते नहीं हैं। उन लोगों की बात पर मुझे एक बात याद आगई। जनक महाराज के समय में एक बार भकाल आ गया। यह नहीं है कि पहले भकाल नहीं आता था। पहले भी आता था धीरे भव भी आता है। लेकिन जनक महाराज बहुत सिसिधर में। क्या घास को पता है जनक महाराज ने क्या किया? उन्होंने पूजा करनी शुरू की। महादेवी उनकी सिसिधरटी को समझ कर बोली कि जनक जाओ लोगों की

मदद करो। तुम हाथ में हल जो धीरे जमीन को जोती, उगाओ। तब जनक महाराज हल लेकर गये धीरे जमीन को जोता। जिस से फिर खूब पैदावार हुई। इसी तरह से डिपार्टमेंट के पास जो आफिसर्स लोग हैं वह फाइलस लेकर कृषि भवन में बैठे रहते हैं। यह नहीं कि जो उन के पास ट्रैक्टर हैं उन को लेकर खेत में जायें धीरे किसानों के सामने मिसाल पेश करे। मैं इस बात को बिल्कुल पसन्द नहीं करती। मैं तो कहती हूँ कि एक एक बड़े आफिसर को एक एक स्टेट देना चाहिए धीरे उसकी जिम्मेदारी वह सम्भालें। जब कोई डाक्टर बनता है तो दवाखानों में रहता है इंजीनियर बनता है तो प्रोजेक्ट में जाकर काम करता है। लेकिन जो एग्रिकल्चरिस्ट बनते हैं, पी० एच० डी० बन जाते हैं फारेन कंट्रीज में जाकर, वह फाइलस लेकर बैठ जाते हैं। यह बहुत बुरी बात है। मैं जानती हूँ कि आफिसर लोग खराब आदमी नहीं हैं जो भी हम यहाँ बोलते हैं उसको वह ध्यान से सुनते हैं। लेकिन उनको जाकर लोगों को अपनी पालिसी को बतलाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जैसे एक मिलिट्री का ब्रिगेडियर होता है। वह पूरी ब्रिगेड को कंट्रोल करता है, उसी तरह से एक एक एग्रिकल्चरिस्ट को 25-25 हजार एकड़ के ऊपर रक्खा जाये। धीरे वह उस काम की देख रेख रखे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि मिनिस्टर को भी एक एक हफ्ता एक एक स्टेट में जा कर रहना चाहिये तब उसको पता चलेगा कि उन किसानों को क्या तकलीफ होती है।

घासके पास इतना रुपया है। घास शहरों में सप्सिडी दे कर भकाल बनवाते हैं। ज्यादा पैसा देकर भनाज बाहर से मंगवाते हैं। स्वेज नहर बन्द हो गई है इस लिये दूसरे रास्ते से घास आठ बस्तु ला रहे हैं यहाँ सप्सिडी देकर भूकानें बनवा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ जो देहातों में गरीब

[ श्रीमती लक्ष्मी बाई ]

लोग रहते हैं जो कि इतनी मेहनत करने हैं अपने हाथ से अपना काम करते हैं वहां पर उनके लिये दूकानें क्यों नहीं बनवाई जाती ? जब भी फेब्रुअरी में शाप्ट बनवाई जाती है तो बड़े बड़े शहरों में बनवाई जाती है। मैं बताना चाहती हूँ कि या तो गावों में भी दूकानें होनी चाहिए या फिर शहरों में भी बन्द होनी चाहिए। प्रायः खाने वालों के लिये मक्खिडी देते हैं, बेचने वालों के लिये सक्खिडी देते हैं, लेकिन फटिलाइजर पर जो कि किसानों के काम आता है, प्रायः ने सक्खिडी हटा दी है। किम तरह से उनका काम चलेगा ? यह बिल्कुल गलत काम हो रहा है। इसके ऊपर प्रायः का ध्यान देना चाहिए। प्रायः दूकानों पर जो मक्खिडी देते हैं उम पर मुझे यह ऐतराज है कि मिर्क शहरों में मक्खिडी रखने में और दूकान खोलने से काम विगड़ना जा रहा है और दूकानों में स्टेक-माउंट हो रहा है। इस वास्ते गाव वाने गाव छोड़ कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। शहरों में राशन के दसो सहाय्यते हैं। इस लिये गाव छोड़ कर लोग चले आ रहे हैं और गाव तबाह होते चले जा रहे हैं। अगर सक्खिडी देनी ही होती है घर भी दी जाये और उधर भी दी जाये नहीं तो बन्द कर दी जाये।

हम आंध्र प्रदेश के लोग कितने अच्छे हैं। प्रायः ने हमारे चीफ मिनिस्टर ने बादा किया था कि हमने राज्यों के लिये प्रायः को 6 लाख टन पैकी देगे। मद्रास, मैसूर, केरल, बिहार वालों को भी खिलाया और मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, उड़ीसा भी है, जिन को प्रायः तक 4 लाख टन दे चुके हैं।

श्री राम सेवक दासबः : उत्तर प्रदेश को भी दे दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : उत्तर प्रदेश में प्रायः की गवर्नमेंट है उन से कहिये।

हम से 4 लाख टन बिना है और 2 लाख टन बाकी है। वहां पर पानी नहीं है। स्पीकर साहब का इलाका है जहां पीने के लिये भी पानी नहीं है। हमारे आंध्र प्रदेश में तीन जगहें हैं। कृष्णा-गोदावरी का इलाका है उन के पास तैलंगाना भी है और रायच-सीमा भी है। यह तीनों बड़े गरीब जिले हैं। जब बाढ़ आती है तो हर तरफ पानी भर जाता है। यहा पर साठ पाच सौ करोड़ रुपया लगा बर बाहर से हमें अनाज मंगाकर खाना खिलाते है, बाढ़ों से हमारी रक्षा करने है, 200 करोड़ रुपया लगा कर लोगों को फेयर प्राइस शाप में सक्खिडी देते है। हम ने 60 करोड़ रुपया लगा दिया है, 25 करोड़ रुपया और चाहिये। हम को यह रुपया दीजिये हम प्रायः का पूरा इन्तजाम कर देंगे। जो जो लोग खाना चाहते है हम उन्हें चावल देगे इस का हम वादा करै है। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती ? प्रायः क्यों मौन बैठ हुए है हम प्रायः से कोई भीष नहीं माग रहे है। हम लोग माग रहे हैं। हमें मालूम नहीं होता है कि आखिर सरकार की पालिसी क्या है अनाज भेजने का पहले तो आर्डर दे देते हैं लेकिन जब बाढ़ में पैसा मागत है तो फिर घुम फुम करते हैं। एथिकल्सर मिनिस्टर को मालूम होना चाहिये कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। जो गाय ज्यादा दूध देने वाली होती है उस को ज्यादा चारा खिलाया जाता है। जो कम दूध देती है उस को कम दो। ऐसी बाब नहीं होनी चाहिये। जो पेट भर खिलाता हो उस की बात न पूछी जाये, उस के माब अच्छा व्यवहार न किया जाये।

एक माननीय सख्तबः . क्या प्रायः मन कांसेस बना रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी बाई : यहां पर लोगों को 99 पैके में चावल मिलता है लेकिन हमें

1 व० 5 घाने में चावल मिलता है। हमारे चीफ़ मिनिस्टर ने चावल क़िया का इस लिये हम चावल दे रहे हैं लेकिन हम को उस के बदले में कुछ तो दो। गेहूँ दो, ज्वार दो। हम मुफ्त तो नहीं मांग रहे हैं बाख़िर 1 लाख 50 हजार टन हम भी तो दे रहे हैं। हमारी डिमांड शूगर की 12 हजार टन की दर महीने की है। हमारे पास शूगर होती है लेकिन उस को एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे यहां शहर होती है लेकिन हमारे ही यहां बह प्राधी कर दी गई है। इतनी कमी तो नहीं होनी चाहिये। हमारा हिस्सा तो हम को मिलना चाहिये।

फूड एंड एग्रीकल्चर को प्राप रखने है। मे मसलवी हू कि एग्रीकल्चर नहीं है प्रम फूड ही रह गई है। एग्रीकल्चर का अन्तर्लव होता है घर मे तमाम सामान रहना खोई बनाना। फूड होता है टेबल पर मजाना। प्रापने एग्रीकल्चर को छोड दिया है और फूड को ही पकड लिया है। प्रापने कारपोरेशन बनाई है और चारह हजार लोग उस मे भरनी किए है—

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या अपना भावग कल जारी रखें। प्रब हाफ एन प्रावर लिया जाएगा।

17.51 hrs.

\*RETRENCHMENT IN FOREIGN OIL COMPANIES

Shri Umanath (Pudukkottai): Mr. Speaker, Sir, the retrenchment in the foreign oil companies has been going headlong since 1960. So far 9,000 employees have been retrenched and many more are to be axed. Ever since the Damle Committee imposed

a slight restriction on the loot of these oil companies, they have resorted to this retrenchment as a way to restore their pre-Damle committee super profits. It goes without saying that it is the Government's responsibility to ban retrenchment as part of their responsibility to prevent the companies' attempts to circumvent the Damle committee's restriction on their super profits but the Government has utterly failed in this regard. Now an enquiry commission has been appointed by the Government. Does this Commission help to resolve this dispute? According to me the appointment of this commission does not at all help to resolve this dispute. What are the crucial issues involved in this dispute? According to me, they are two. One is whether the business and financial conditions of these companies warrant the creation of any redundancy of labour; if not, how to ensure job security against the onslaught of the foreign oil companies? The second issue is, how to compel the management to stop retrenchment during the pendency of the determination of the main dispute? Let us take the question of maintaining the status quo during the pendency. It is a sorry tale of the foreign oil companies defying their own assurances, defying the union, defying the government and defying the labour relations. In short it is perpetrating humiliation in this country while the Government just kept looking on, putting up an appearance of helplessness. In 1965, when the first tripartite to ensure job security was appointed, Shri Sanjivayya assured this House that status quo would be maintained. The companies trampled under foot this assurance and went on retrenching people. Then again in October 1966, when the Labour Commissioner of West Bengal fixed the conciliation for the 17th of that month, these companies assured that status quo would be maintained and got extension of that date upto the 20th. But before the coa-